सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार
"इच्छाएं अनंत है सब की पूर्ति संभव नहीं ...!!"
अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–137 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, शनिवार 06 जून 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

22 साल बाद राहुल गांधी मॉडल पर चलती दिख रही है कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्यसभा : मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी से बदला सियासी समीकरण

नमित शुक्ला / नईदिल्ली

कांग्रेस में दो दशक से अधिक के सक्रिय राजनीतिक जीवन के बाद अब राहुल गांधी के फैसलों पर पार्टी में मुहर लगती दिख रही है। मध्यप्रदेश से मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाना इसी बदलाव का संकेत माना जा रहा है।

विश्वस्त चेहरे को तरजीह

मीनाक्षी नटराजन लंबे समय से राहुल गांधी की टीम का हिस्सा रही हैं। 2006 में जब राहुल राष्ट्रीय महासचिव और युवा कांग्रेस के प्रभारी बने, तब नटराजन उनके साथ संबद्ध सचिव थीं। 2009 में मंदसौर से लोकसभा टिकट भी उन्हें राहुल की पसंद पर मिला था। एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकीं नटराजन फिलहाल कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य और तेलंगाना की प्रभारी हैं।

मध्यप्रदेश का समीकरण

2024 के राज्यसभा चुनाव में अगर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अशोक सिंह की जगह नटराजन को समर्थन देते, तो दिग्विजय सिंह तीसरी बार उच्च सदन पहुंच सकते थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर 2024 में अशोक सिंह की एंट्री न होती, तो आज अनुभव यानी ऐश्वर्य को तरजीह मिलती। कांग्रेस पारंपरिक रूप से अनुभव को महत्व देती रही है—83 वर्षीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसका उदाहरण हैं।

अब राहुल गांधी ने हरियाणा के करमवीर सिंह बौद्ध वाले फॉर्मूले की तर्ज पर मध्यप्रदेश में नटराजन को उतारा है। पार्टी को उम्मीद है कि प्रदेश नेतृत्व का पूरा समर्थन मिलेगा। 2009 में भी मंदसौर से नटराजन की उम्मीदवारी पर दिग्विजय सिंह ने स्थानीय नेताओं से कहा था—"जिताने के लिए मेहनत करो"। इस बार भी कांग्रेस विधायकों को वैसा ही संदेश मिलने की चर्चा है।

भाजपा की रणनीति

भाजपा ने मध्यप्रदेश से रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी में अटकलें हैं कि कांग्रेस के खिलाफ तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतारा जाए या निर्दलीय को समर्थन दिया जाए। भाजपा कैडर आधारित पार्टी है और 22 साल से प्रदेश में सत्ता में है। 1982 में लालकृष्ण आडवाणी भी मध्यप्रदेश से ही राज्यसभा पहुंचे थे। पार्टी अक्सर बाहरी राज्यों से उम्मीदवार लाती रही है, जिनका कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रदेश से जुड़ाव कम ही दिखता है। हाल में दो केंद्रीय राज्य मंत्री भी राज्यसभा सदस्य थे, जो केरल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हार गए थे।

क्या बदला कांग्रेस में

कर्नाटक में डीके शिवकुमार की ताजपोशी हो या केरल में वीडी सतीशन को जिम्मेदारी—राहुल गांधी के फैसलों पर अब अंतिम मुहर लग रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर कांग्रेस में अब तक मार्गदर्शक मंडल नहीं बन पाया। इसकी वजह कांग्रेस का ढांचा और भाजपा का कैडर आधार माना जाता है।

मध्यप्रदेश कांग्रेस का अनुभवी नेतृत्व दशकों से गांधी परिवार के साथ रहा है। ऐसे में नटराजन की जीत में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की भूमिका अहम मानी जा रही है। आलाकमान भी सिंहों के अभ्यारण्य कहे जाने वाले मध्यप्रदेश की सियासी तासीर से वाकिफ है। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि क्या मध्यप्रदेश में भी हरियाणा वाला फॉर्मूला कामयाब होगा और क्या राहुल गांधी का विश्वस्त चेहरा दांव राज्यसभा तक पहुंच पाएगा।

डायल 112 ने बचाई महिला की जान, राजनांदगांव पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने

जंगल से भागकर पहुंची घायल महिला को समय पर मिली मदद, एसपी अंकिता ने टीम को किया सम्मानित

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

राजनांदगांव पुलिस की डायल 112 टीम ने तत्परता और साहस का परिचय देते हुए एक महिला की जान बचाई। जंगल से भागकर गांव पहुंची घायल महिला को पुलिस ने सुरक्षित थाने पहुंचाया और तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा।

पति पर हमले का आरोप

डायल 112 को सूचना मिली थी कि एक घायल महिला जंगल की ओर से भागते हुए गांव पहुंची है। टीम तत्काल मौके पर पहुंची। महिला ने बताया कि उसका पति उसे जान से मारने की नीयत से जंगल ले गया था। मारपीट के दौरान वह जान बचाकर भाग निकली। पुलिस वाहन देखकर पति मौके से फरार हो गया।

तत्काल मिली मदद

डायल 112 टीम ने महिला को सुरक्षित अभिरक्षा में लेकर थाना पहुंचाया। उसकी हालत देखते हुए तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ में भर्ती कराया गया। महिला की समय पर मदद कर पुलिस ने एक बड़ी अनहोनी टाल दी।

एसपी ने किया सम्मानित

उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा ने आरक्षक दीपेश मुद्दनकर और डायल 112 चालक रविंद्र देवांगन को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और रक्षित निरीक्षक लोकेश कुमार कसेर मौजूद रहे।

राजनांदगांव पुलिस का यह कदम बताता है कि वर्दी के पीछे एक संवेदनशील दिल भी धड़कता है। किसी भी आपात स्थिति में डायल 112 आपकी मदद के लिए 24 घंटे तैयार है।

खुर्सीपार में 15 टन से अधिक अवैध कोयला जब्त, फर्जी बिल बनाने वाले सहित 3 गिरफ्तार

पुलिस ने 3 लाख का कोयला और 3 मोबाइल किए बरामद, फर्जीवाड़े का पर्दाफाश

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

दुर्ग पुलिस ने खुर्सीपार में बड़ी कार्रवाई करते हुए 15.530 टन अवैध कोयला जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत फर्जी जीएसटी बिल बनाने वाले गिरोह के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त कोयले की कीमत 3 लाख रुपये से अधिक बताई गई है।

मुखबिर की सूचना पर दबिश

एसीसीयू दुर्ग और थाना खुर्सीपार पुलिस की संयुक्त टीम को सूचना मिली थी कि खुर्सीपार गेट में विजय केसरवानी भारी मात्रा में कोयले का अवैध भंडारण कर चोरी छिपे बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी। जांच के दौरान आरोपी विजय कुमार केसरवानी के कब्जे से 15.530 टन कोयला, कांटा तराजू और अन्य दस्तावेज बरामद हुए।

फर्जी बिल से गुमराह करने की कोशिश

पूछताछ में आरोपी ने वैध स्वामित्व के दस्तावेज दिखाकर खुद को व्यापारी बताया। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और वैज्ञानिक जांच से दस्तावेजों का सत्यापन कराया। जांच में जीएसटी बिल, परिवहन अभिलेख और अन्य रिकॉर्ड कूटरचित व फर्जी पाए गए।

बिल बनाने वाला गिरोह भी पकड़ाया

विवेचना में सामने आया कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने में अन्य लोगों की भूमिका थी। वित्तीय लेनदेन, डिजिटल भुगतान और मोबाइल संचार के विश्लेषण से फर्जी जीएसटी बिल बनाने वाले राजकुमार मिश्रा और उसके सहयोगी सुनील शर्मा की संलिप्तता मिली। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर दोनों को भी गिरफ्तार किया गया।

तीन आरोपी गिरफ्तार

थाना खुर्सीपार में अप.क्र. 208/2026, धारा 317(4), 336(3), 340(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 1. विजय कुमार केसरवानी, 48 वर्ष, निवासी खुर्सीपार मार्केट, 2. राजकुमार मिश्रा, 46 वर्ष, निवासी प्रियंका नगर खुर्सीपार, 3. सुनील शर्मा, 50 वर्ष, निवासी 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड जामुल शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों से 3 मोबाइल भी जब्त किए हैं।

पुलिस बरामद कोयले के वास्तविक स्रोत, स्वामित्व और परिवहन व्यवस्था की जांच कर रही है। मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल जारी है।

कोटमी सराफा हत्याकांड का आरोपी झारखंड से गिरफ्तार, लूट का माल बरामद

पेंड्रा। कोटमी साप्ताहिक बाजार में सराफा व्यवसायी प्रदीप सोनी की दिनदहाड़े हत्या और लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतरराज्यीय अभियान के तहत घटना के एक आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से लूटे गए सोना–चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री बरामद की गई है। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज रामगोपाल गर्ग के निर्देशन में जिला पुलिस, जिला साइबर सेल जीपीएम और रेंज साइबर थाना की संयुक्त टीम तकनीकी साक्ष्य और डिजिटल ट्रैकिंग के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी क्रम में

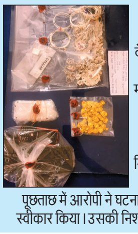

3 जून 2026 को जसीडीह, जिला देवघर (झारखंड) से राहुल उर्फ मनीष मंडल (30), निवासी विजय नगर, थाना बांका, जिला बांका (बिहार) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने घटना में शामिल होना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर उसके हिस्से के लूटे गए सोना–चांदी के आभूषण, चार मोबाइल हैंडसेट, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और अन्य सामग्री बरामद की गई है।

गौरतलब है कि कोटमीकला साप्ताहिक बाजार में सराफा व्यवसायी प्रदीप सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और आभूषणों से भरा बैग लूट लिया गया था। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश था। पुलिस ने बताया कि मामले में संलिप्त अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस इस कार्रवाई को मामले के खुलासे की दिशा में अहम मान रही है।

त्वरित टिप्पणी

नीट पेपर लीक से फैजल खान तक, भटकती बहस, छूटते सवाल

आलोक तिवारी

नीट पेपर लीक लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा सीधा सवाल था। जब लगातार परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए, तो देशभर के युवा, शिक्षक और अभिभावक एकजुट होकर NTA और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर जवाब मांग रहे थे। मांग साफ थी : दोषी कौन, जांच कहां तक पहुंची और भविष्य में लीक कैसे रुकेगा? सरकार और शिक्षा मंत्रालय बैकफुट पर थे। पहली बार छात्र राजनीति से ऊपर उठकर अपने हक के लिए एक स्वर में बोल रहे थे।

मुद्दे का रुख कैसे बदला

बहस का पहला मोड़ तब आया जब बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के स्टूडियो में शिक्षकों पर तीखी टिप्पणियां हुईं। नतीजा यह हुआ कि चर्चा पेपर लीक और जवाबदेही से हटकर मीडिया बनाम शिक्षक हो गई। जब सोशल मीडिया पर इस रुख की आलोचना बढ़ी, तो विमर्श रातोंरात कोचिंग माफिया पर शिफ्ट कर दिया गया। जांच का फोकस परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों से हटकर कोचिंग संस्थानों पर चला गया। इसी बीच बिहार में दो चर्चित शिक्षकों—खान सर और ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर—के बीच विवाद को केंद्र में लाया गया। एक शिक्षक की गिरफ्तारी हुई। जो छात्र कल तक नीट पेपर लीक के खिलाफ एक साथ खड़े थे, वे अब अपने–अपने पसंदीदा शिक्षक के समर्थन में खेमों में बंट गए। पेशेवर मतभेद को असाधारण विवाद की तरह पेश किया गया।

जाति और धर्म का प्रवेश

जब मामला ठंडा पड़ने लगा, तो सोशल मीडिया पर जातिगत पहचान उछाली गई। छात्रों को याद दिलाया गया कि कौन शिक्षक किस जाति से है। और फिर सबसे संवेदनशील मोड़ आया—धार्मिक ध्रुवीकरण। कई न्यूज चैनलों और यूट्यूब थंबनेल में खान सर को अचानक फैजल खान लिखा जाने लगा। दो शिक्षकों का विवाद देखते–देखते धर्म के चश्मे से दिखाया जाने लगा। बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनलों का दायित्व तथ्य, जांच और जवाबदेही पर टिकना है। जब प्राइम टाइम का फोकस परीक्षा की शुचिता के बजाय शिक्षकों की निजी पहचान पर चला जाए, तो असल मुद्दा पीछे छूट जाता है। सोशल मीडिया पर भी व्यूज और एल्गोरिद्म की होड़ में थंबनेल भड़काऊ होते गए। क्लिक की दौड़ में विमर्श की गंभीरता खो गई। नतीजा : चर्चा लीक के नेटवर्क से हटकर जाति और धर्म पर आ गई।

इस पूरी कड़ी में सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र का है जो सालों की मेहनत के बाद परीक्षा देता है। उसकी ऊर्जा सड़क, धरने और आपसी बहस में खर्च हो रही है। शिक्षा के मंदिर में जब जाति–धर्म की पहचान मुख्य विमर्श बन जाए, तो व्यवस्था पर उठने वाले सवाल दब जाते हैं। सवाल अब भी वही हैं : नीट पेपर लीक की जांच कहां तक पहुंची? दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई? NTA की कार्यप्रणाली में क्या सुधार किए गए? भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए क्या ठोस तंत्र बना? बिहार की घटना, गिरफ्तारी या किसी शिक्षक का नाम बदलकर लिखना, ये खबर हो सकते हैं। पर इन्हें मुख्य खबर बनाकर पेपर लीक को साइड स्टोरी नहीं बनाया जा सकता। बड़े चैनलों और सोशल मीडिया मंचों को तय करना होगा कि वे बहस को भटकाएंगे या सवालों को जिंदा रखेंगे।

छात्रों को न्याय सिर्फ नारों से नहीं, जवाबदेही से मिलेगा। इसलिए विमर्श को वापस परीक्षा सुधार, पारदर्शी जांच और दोषियों पर कार्रवाई पर लाना ही एकमात्र रास्ता है। वरना हर लीक के बाद एक नई स्क्रिप्ट लिखी जाएगी और असल मुजरिम पर्दे के पीछे ही रह जाएंगे।

दिग्विजय क्लब की दुकानों पर आरटीआई से उठे सवाल

15 लाख के सरकारी अनुदान, पंजीयक की अनुमति और सूचना न देने पर जांच की मांग

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

दिग्विजय क्लब में निर्मित दुकानों को लेकर दायर आरटीआई आवेदन से कई सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि निर्माण, अनुदान के उपयोग और व्यावसायिक गतिविधि की जानकारी छुपाई जा रही है।

पहला सवाल: 15 लाख के अनुदान का उपयोग

सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ शासन ने पूर्व में दिग्विजय क्लब को निर्माण कार्य के लिए 15 लाख रुपये का अनुदान दिया था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह राशि इन्हीं दुकानों के निर्माण में खर्च की गई। यदि हां, तो सरकारी धन से बनी दुकानों का आवंटन किस आधार पर हुआ और किराया किस खाते में जा रहा है, यह स्पष्ट नहीं है। आरटीआई में वित्तीय विवरण नहीं दिया गया।

दूसरा सवाल: पंजीयक की अनुमति

सूत्रों का कहना है कि फर्म्स एंड सोसायटी के पंजीयक से व्यावसायिक निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई। नियमानुसार पंजीकृत क्लब को मूल गतिविधियों से अलग व्यावसायिक निर्माण के लिए पंजीयक से संशोधन या अनुमति लेना जरूरी होता है। अनुमति शुल्क जमा किए बिना निर्माण अवैध की श्रेणी में आता है।

तीसरा सवाल: जानकारी न मिलना

कलेक्टर दिग्विजय क्लब के पदेन अध्यक्ष हैं। आरटीआई आवेदन कलेक्टर कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को दिया गया था। नगर निगम ने निर्माण अनुज्ञा का नक्शा उपलब्ध करा दिया, लेकिन क्लब से वित्तीय विवरण, निविदा, ठेकेदार का ब्योरा, आवंटन सूची, किराया विवरण और भूमि दस्तावेज नहीं मिले।

क्या मिला, क्या नहीं

मिला: नगर निगम से निर्माण अनुज्ञा नक्शा।
नहीं मिला: 15 लाख अनुदान का हिसाब, पंजीयक की अनुमति का प्रमाण, निविदा–ठेकेदार विवरण, आवंटन सूची, किराया विवरण, पूर्णता प्रमाण पत्र, भूमि खसरा।

आगे क्या

आवेदनकर्ता जितेन्द्र जैन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील, फर्म्स एंड सोसायटी पंजीयक से क्लब के बायलॉज की जांच, 15 लाख अनुदान के उपयोग का ऑडिट और लोकायुक्त से निष्पक्ष जांच की मांग की है। हितों के टकराव को देखते हुए स्वतंत्र अधिकारी से जांच कराने की बात भी कही गई है। फिलहाल क्लब प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है। मामला अब आरटीआई कानून के पालन, सरकारी अनुदान के उपयोग और पंजीयक नियमों की अनदेखी के आरोपों से जुड़ गया है।

छुईखदान में पुलिसकर्मी ने घर में की आत्महत्या, फंदे पर मिली लाश

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

जिले के छुईखदान थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक शीतल यादव की आत्महत्या की खबर से पुलिस महकमे में शोक और स्तब्धता का माहौल है। शनिवार तड़के उनका शव खैरागढ़ शहर के दाऊचौरा स्थित निवास में फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शीतल यादव अपने परिवार के साथ वार्ड क्रमांक 16 स्थित दाऊचौरा क्षेत्र में निवासरत थे।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात परिवार के सदस्य अपने–अपने कमरों में सोने चले गए थे, जबकि वे घर के हॉल में थे। शनिवार सुबह करीब चार बजे उनकी पत्नी की नींद खुली तो उन्होंने शीतल यादव को गमछे के सहारे फंदे से लटका देखा। यह दृश्य देखकर परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही खैरागढ़ पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की। दुर्ग से फोरेंसिक टीम बुलाई गई है, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

पेड़ लगाना ही पर्यावरण में असली निवेश, विश्व पर्यावरण दिवस पर ब्रह्माकुमारी आशा दीदी का संदेश

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सेक्टर-7 के पीस ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी आशा दीदी ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा हमारा श्रेष्ठ और सबसे बड़ा परमधर्म है। उन्होंने कहा, हम बैंक, पोस्ट ऑफिस और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए हर व्यक्ति को पर्यावरण में निवेश करना चाहिए। पेड़ लगाकर और उनकी देखभाल करके ही हमारा भविष्य और धरती सुरक्षित रहेगी।

आशा दीदी ने कहा कि एसी और कूलर लगाना गर्मी से बचने का स्थायी हल नहीं है। वृक्षारोपण ही जरूरी है। साथ ही वायुमंडल को शुद्ध रखने के लिए मन में श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प करना भी आवश्यक है, तभी प्रकृति सहयोगी बनेगी।

पर्यावरण योद्धाओं का सम्मान

कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान किया गया। पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी नरेंद्र सिंह पटेल को सम्मानित किया गया। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के साथ मिलकर जिले के 65 स्कूलों में बच्चों के हाथों लगभग 5000 पौधे लगवाए थे, जो आज वृक्ष बन चुके हैं।

पर्यावरण, पशु कल्याण एवं पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में गणेशराम सुथार का सम्मान हुआ। उन्होंने पक्षियों के लिए बहु-स्तरीय पक्षी आवास टॉवर बनवाया है, जिसमें बने सुरक्षित घोंसला-स्थलों में वर्तमान में 700 से अधिक पक्षियों को आश्रय मिला है।

वहीं विगत 9 वर्षों से घायल और बेसहारा पशुओं के बचाव व उपचार के लिए कार्यरत छत्तीसगढ़ एनिमल सेवियर संस्था और एनिमल बर्थ कंट्रोल संचालन के लिए डॉ. अंजलि सिंह को सम्मानित किया गया।

सांस्कृतिक प्रस्तुति और संदेश

डिवाइन ग्रुप के बच्चों ने पर्यावरण की वर्तमान स्थिति पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। भिलाई इस्पात संयंत्र के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (एचआर) पवन कुमार ने ब्रह्माकुमारी संस्था के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में डॉ. राखी, डॉ. अंजलि, डॉ. नरेंद्र पटेल, स्वच्छता ही सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद साहू, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह सहित बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे। अंत में सभी ने राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से प्रकृति के पांचों तत्वों को शांति के प्रकंपन भेजे।

खास खबर

यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने मंत्री यादव ने किया दौरा, शहर के आंतरिक मागी का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में ट्रैफिक कंट्रोल एवं यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने आज प्रदेश के केबिनेट मंत्री एवं दुर्ग शहर के विधायक गजेन्द्र यादव ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों एवं इंजीनियरों के साथ विभिन्न चौक-चौराहों और प्रमुख मार्गों का स्थल निरीक्षण किये। निरीक्षण के दौरान पोटिया चौक से बस्ती तक मार्ग, बोरसी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र, बस स्टैंड से गणेश मंदिर रोड, नयापारा चौक से आनंद सरोवर तक मार्ग, बघेरा रोड सहित विभिन्न स्थानों का अवलोकन कर यातायात सुधार एवं सड़क चौड़ीकरण की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री श्री यादव ने कहा कि दुर्ग शहर का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसके अनुरूप सड़क एवं यातायात अधोसंरचना का विकास आवश्यक है। नागरिकों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं बाधारहित आवागमन उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है।

निरीक्षण के दौरान बोरसी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण, नयापारा चौक से आनंद सरोवर तक सड़क चौड़ीकरण, बस स्टैंड से गणेश मंदिर रोड में मोड़ के पास सड़क चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और सौंदर्यीकरण करने संबंध में आवश्यक तकनीकी सर्वे कर शीघ्र इस्टीमेट तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर यातायात दबाव को कम करने, सड़क सुरक्षा बढ़ाने तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूर्ण काययीजना तैयार करने पर भी जोर दिया गया।

केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने अधिकारियों से कहा कि जिन क्षेत्रों में सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण नागरिकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहां प्राथमिकता के आधार पर काययीजना तैयार की जाए। उन्होंने सड़क चौड़ीकरण के साथ-साथ रात्रि में पर्याप्त रौशनी, सड़क किनारे जल निकासी, पैदल यात्रियों की सुविधा, यातायात संकेतक, सभी चौक चौराहे का सौंदर्यीकरण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को भी प्रस्तावों में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए निरंतर मैदानी निरीक्षण कर रहे हैं तथा जनता की सुविधा से जुड़े प्रत्येक विषय पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में इन कार्यों के पूर्ण होने से शहर की यातायात व्यवस्था और अधिक सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित होगी, जिससे हजारों नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

कल से शुरू होगा सर्वे : पीडब्लूडी के इंजिनियर ने बताया की शहर के आंतरिक मागी के मजबूतीकरण चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाना है, बजट में प्रस्तावित कार्यों का कल से सर्वे प्रारंभ किया जाएगा जिसमें हेमंचंद यूनिवर्सिटी से पुराना हाउसिंग चौक बोरसी तक चौड़ीकरण व मजबूतीकरण का सर्वे कल से शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही महाराजा चौक से पहिरावा बुटीक तक भी सर्वे होगा। इसके अलावा साईं मंगलम के आगे से से केनाल होते बोरसी साहू होटल बोरसी चौक तक, नयापारा से आनंद सरोवर मोड़ तक, स्मृति नगर मुख्य मार्ग से कातुलबोर्ड सड़क का भी इस्टीमेट शीघ्र ही तैयार किया जाएगा।

जल संसाधन विभाग और रिसाली निगम के संयुक्त अभियान में शासकीय भूमि कराई अतिक्रमण मुक्त

हनोदा माइनर नहर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जल संसाधनों के संरक्षण तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुर्ग जिले में हनोदा माइनर नहर क्षेत्र में विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में जल संसाधन विभाग एवं नगर पालिक निगम रिसाली की संयुक्त टीम ने नहर क्षेत्र एवं विभागीय स्वामित्वाधीन शासकीय भूमि पर वर्षों से किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।

हनोदा माइनर नहर डी.पी.एस. स्कूल से वी.आई.पी. नगर तक नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह नहर क्षेत्र जल प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नहरों एवं उनसे संबद्ध शासकीय भूमि का संरक्षण जनहित से जुड़ा विषय है। इन क्षेत्रों में किए गए अतिक्रमण न केवल शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जे की श्रेणी में आते हैं, बल्कि नहरों के अनुरक्षण, निरीक्षण एवं मरम्मत कार्यों में भी बाधा उत्पन्न करते हैं।

प्रशासन द्वारा कार्रवाई से पूर्व संबंधित अतिक्रमणकर्ताओं को स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए संयुक्त दल ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अभियान के दौरान नगर पालिक निगम रिसाली एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और कमर्चारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। कार्रवाई को सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया, जिससे नहर क्षेत्र को उसके मूल स्वरूप में पुर्नस्थापित किया जा सका।

कार्यपालन अभियंता आशुतोष सारश्वत ने बताया कि जल संसाधन विभाग के अधीन नहरों, जल संरचनाओं, अनुरक्षण मार्गों तथा शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र की सभी नहरों एवं शासकीय परिसंपत्तियों की सतत निगरानी की जा रही है और जहां भी अतिक्रमण पाया जाएगा, वहां बिना किसी भेदभाव के वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि शासकीय भूमि एवं जल संरचनाएं सार्वजनिक संपत्ति हैं, जिनका संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है। इन परिसंपत्तियों का सुरक्षित एवं उद्देश्यपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। जल संसाधन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नहरों, शासकीय भूमि तथा अन्य सार्वजनिक उपयोगिता की संरचनाओं पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें और इनके संरक्षण में प्रशासन का सहयोग करें। सार्वजनिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण से ही जनहित एवं विकास कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित की जा सकती है।

0 से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन के लिए जिले में चलेगा व्यापक सर्वे अभियान

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समग्र शिक्षा अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन एवं सर्वेक्षण के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने शून्य से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन हेतु जिले में व्यापक सर्वे अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस अभियान के लिए समाज कल्याण, जिला शिक्षा अधिकारी, एडीपीओ, डीएमसी, महिला एवं बाल विकास विभाग को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में समग्र शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह सर्वेक्षण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में वर्णित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर से विकासखंड, संकुल एवं विद्यालय स्तर तक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सर्वे के दौरान दृष्टिबाधित, कम दृष्टि, श्रवण बाधित, कुष्ठ रोग से मुक्त होने के बावजूद शारीरिक विकृति से प्रभावित, जीर्ण स्नायविक स्थिति सहित अन्य दिव्यांगताओं से प्रभावित बच्चों की पहचान की जाएगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना, उनका नामांकन सुनिश्चित करना तथा आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक सहयोग एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि यह सर्वे व्यापक स्तर पर संचालित किया जाए। इसके तहत विकासखंड एवं क्लस्टर स्तर पर बीआरपी एवं स्पेशल एजुकेटर द्वारा सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन सहित जमीनी स्तर के कमर्चारियों को प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही प्रत्येक विद्यालय से एक शिक्षक को इंक्लूसिव एजुकेशन एंबेसडर के रूप में चिन्हित कर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

विश्व कीट दिवस : कीट मुक्त वातावरण बनाए रखना आज की प्राथमिकता

मोहम्मद मजहर नदीम-दुर्ग, छत्तीसगढ़ प्रतिनिधि-पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया पुणे

हर साल 6 जून को विश्व कीट दिवस (World Pest Day) मनाया जाता है। इसके साथ ही हर साल 6 जून से 20 जून तक विश्व कीट दिवस पखवाड़ा भी मनाया जाता है। जिसमें कीट नियंत्रण के प्रति जनजागरुकता के आयोजन किए जाते रहे हैं। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण की दृष्टि से लोगों में कीट नियंत्रण (Pest Control) की महत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2017 में चीन, अमेरिका और यूरोप के कीट नियंत्रण संगठनों द्वारा मिलकर की गई थी।

कीट नियंत्रण क्यों जरूरी है ? : कीट, जैसे मच्छर, चूहे, कॉकरोच और दीमक, न सिर्फ हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि कई बार ये खतरनाक बीमारियां भी फैलाते हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और प्लेग जैसी बीमारियों के लिए ये कीट ही मुख्य वाहक होते हैं। साथ ही, भंडारण में रखे अनाज को दीमक और अन्य कीट नष्ट कर देते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा पर संकट खड़ा हो जाता है।

महामारी और कीट नियंत्रण : कोविड-19 महामारी के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण में कीट नियंत्रण सेवाएं कितनी आवश्यक हैं। अस्पतालों, होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर कीट मुक्त वातावरण बनाए रखना आज की प्राथमिकता बन गई है।

पर्यावरण के अनुकूल समाधान की आवश्यकता : हालांकि कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए अब बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक कीटनाशक, और एकीकृत कीट प्रबंधन जैसे विकल्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

आम जनता की भूमिका : साफ-सफाई रखना, घरों में पानी जमा न होने देना, अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखना जैसे छोटे कदम भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही, प्रमाणित कीट नियंत्रण सेवाओं का समय-समय पर उपयोग करना भी जरूरी है। विश्व कीट दिवस सिर्फ कीट नियंत्रण उद्योग के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक अवसर है—स्वस्थ जीवन और सुरक्षित फसलों की दिशा में सोचने और कार्य करने का। आज के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम पर्यावरण-सम्मत और वैज्ञानिक तरीकों से कीट नियंत्रण करेंगे। कीट नियंत्रण के क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती मच्छरों की है। अध्ययन से यह बात सामने आई है कि मच्छर हर साल 10 लाख मनुष्यों का शिकार करते हैं।

दुनियाभर में दस में एक व्यक्ति मच्छरों से संक्रमित : आज, 125 से अधिक वर्षों के बाद, मच्छर जनित बीमारियां हर साल दस लाख से अधिक लोगों को मारती हैं और 700 मिलियन लोगों को संक्रमित करती हैं। पूरी दुनिया में लगभग दस में से एक व्यक्ति मच्छरों की वजह से संक्रमित होता है। जलवायु परिवर्तन, वैश्वीकरण और शहरीकरण के कारण इन बीमारियों के फैलने की गति बढ़ रही है, इसलिए लोगों के लिए जोखिमों के बारे में जागरूक होना और कार्रवाई करना पहले से कहीं ज़्यादा जरूरी है। यही कारण है कि आज वैश्विक स्तर पर मच्छर जनित बीमारियों को लेकर सर्वाधिक गंभीरता बरती जाती है। आज जरूरत इस बात की है कि हम मच्छर जनित बीमारियों के कारण होने वाले भय और पीड़ा से मुक्त दुनिया बनाने में मदद करें।

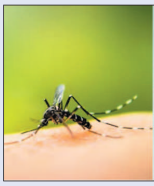

पेस्ट कंट्रोल प्रमुख उपाय : दुनिया में किसी भी अन्य जीव की तुलना में मनुष्य मच्छरों से सबसे अधिक पीड़ित हैं। मच्छर मुख्य रूप से मलेरिया, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया वायरस, जापानी इंसेफेलाइटिस, जीका बुखार, पीला बुखार, लसीका फाइलेरिया (एलिफेंटिएसिस), रॉस नदी बुखार, पूर्वी अश्वारोही इंसेफेलाइटिस, वेस्ट नील विषाणु और सेंट लुईस इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियां फैलाते हैं। इन सभी में लक्षण लगभग एक से होते हैं।

मच्छर जनित बीमारियों में किसी भी तरह के लक्षण मरीज पर दिखने के बाद सबसे जरूर है कि हम उसे तत्काल अस्पताल ले जाएं और उपचार शुरू करवाएं। इसके साथ-साथ हम अपने आसपास के वातावरण को कीटाणुरहित रखने भी पहल करें। इनमें प्रमुख उपाय पेस्ट कंट्रोल है।

जागरूकता के लिए जरूरी : मच्छर जनित बीमारियों जागरूकता के लिए हमें सभी दिशाओं में कार्य करने की जरूरत है। जिसमें मच्छरों का ऐतिहासिक प्रभाव, जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नए क्षेत्रों के लिए उनका बढ़ता खतरा लोगों को बताया जाए। नवीन समाधान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, और मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में स्थानीय समुदायों को शामिल करने और जागरूकता बढ़ाने प्रयास किया जाए। मुख्यधारा और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाई जाए। प्रौद्योगिकी और विज्ञान की नवीनतम जानकारी प्रदान की जाए। जन जागरूकता में स्थानीय लोगों को शामिल किया जाए।

राज्याभिषेक से राष्ट्राभिषेक तक : छत्रपति शिवाजी महाराज की अमर प्रेरणा

6 जून छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक

आचार्य डॉ. अजय आर्य

भारत के इतिहास में 6 जून 1674 केवल एक तिथि नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जागरण का दिवस है। रायगढ़ के दुर्ग पर संपन्न छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक वस्तुत: स्वराज्य, स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्मिता का अभिषेक था। उस दिन केवल एक राजा का राज्याभिषेक नहीं हुआ था, बल्कि पराधीन मानसिकता के विरुद्ध स्वतंत्र चिंतन, जनकल्याणकारी शासन और राष्ट्रधर्म की स्थापना का उद्घोष हुआ था।

छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन भारतीय संस्कृति के उन आदर्शों का साकार रूप है जिनमें शक्ति और शील, पराक्रम और करुणा, शासन और सेवा का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। वे केवल एक विजेता नहीं थे; वे राष्ट्रनिर्माता, कुशल प्रशासक, दूरदर्शी रणनीतिकार और उच्च मानवीय मूल्यों से संपन्न लोकनायक थे।

शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति उनके मातृसंस्कार थे। राजमाता जीजाबाई ने बालक शिवाजी को केवल वीरता का पाठ नहीं पढ़ाया, बल्कि धर्म, न्याय, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के संस्कार भी दिए। उन्होंने अपने पुत्र के मन में यह भावना जगाई कि राज्य का उद्देश्य सत्ता-सुख नहीं, बल्कि लोकमंगल होना चाहिए। यही कारण है कि शिवाजी का संपूर्ण जीवन राजधर्म और जनधर्म का अनुपम उदाहरण बन गया।

युवा शिवाजी ने जब तोरणा दुर्ग पर अधिकार स्थापित किया, तब वह केवल एक सैन्य विजय नहीं थी। वह स्वराज्य के स्वप्न की पहली उद्घोषणा थी। इसके बाद प्रतापगढ़, राजगढ़, सिंहगढ़, पुरंदर और रायगढ़ जैसे दुर्ग स्वतंत्रता के प्रतीक बनते गए। शिवाजी महाराज ने समझ लिया था कि राष्ट्र की सुरक्षा केवल सैनिक शक्ति से नहीं, बल्कि संगठन, आत्मविश्वास और जनसमर्थन से होती है।

उनके जीवन का एक अत्यंत प्रेरक प्रसंग आगरा से जुड़ा है। औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाकर उनकी राजनीतिक शक्ति को समाप्त करने का प्रयास किया, किंतु शिवाजी महाराज ने असाधारण धैर्य, बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देते हुए वहाँ से निकलकर यह सिद्ध कर दिया कि परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों, आत्मविश्वास और विवेक के सामने वे टिक नहीं सकतीं। यह प्रसंग आज भी युवाओं को सिखाता है कि संकट से घबराना नहीं, बल्कि उसका समाधान खोजना नेतृत्व का गुण है।

उनके चरित्र की महानता का दूसरा उदाहरण नारी सम्मान के प्रति उनकी दृष्टि में दिखाई देता है। युद्धों के दौर में भी उन्होंने महिलाओं की गरिमा को सर्वोच्च महत्व दिया। उनकी सेना के लिए स्पष्ट आदेश था कि किसी भी स्त्री, बालक या निहत्थे व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। यह केवल प्रशासनिक आदेश नहीं था, बल्कि उनके व्यक्तित्व की नैतिक ऊँचाई का प्रमाण था।

शिवाजी महाराज ने शासन को जनसेवा का माध्यम माना। किसानों की सुरक्षा, व्यापार की उन्नति, न्यायपूर्ण कर व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता उनके शासन की विशेषताएँ थीं। उनका मानना था कि राज्य की वास्तविक शक्ति उसकी संतुष्ट और सुरक्षित प्रजा में निहित होती है। यह विचार आज भी सुशासन का मूल मंत्र माना जा सकता है।

उनकी युद्धनीति में भी राष्ट्रहित सर्वोपरि था। उन्होंने गुरिल्ला युद्धकला को नई ऊँचाइयाँ प्रदान कीं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने यह सिद्ध किया कि बुद्धिमत्ता और संगठन क्षमता के सामने विशाल सेनाएँ भी पराजित हो सकती हैं। उनका जीवन हमें बताता है कि विजय केवल शक्ति से नहीं, बल्कि रणनीति और आत्मविश्वास से प्राप्त होती है।

छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू स्वाभिमान के महान प्रतीक थे। किंतु उनका हिंदुत्व संकीर्णता का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक गौरव, सहिष्णुता और मानवता का प्रतीक था। उनका संघर्ष किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं था, बल्कि अन्याय, अत्याचार और दमन के विरुद्ध था। यही कारण है कि उनके प्रशासन में विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों को समान सम्मान प्राप्त था।

शिवाजी महाराज के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। उनका विश्वास था कि प्रजा का सुख ही शासक का वास्तविक सुख है। यह विचार केवल राजधर्म का नहीं, बल्कि लोकसेवा का सर्वोच्च सिद्धांत है। उन्होंने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि सत्ता का उद्देश्य प्रभुत्व नहीं, उत्तरदायित्व है।

यदि हम वैदिक दृष्टि से देखें तो शिवाजी महाराज का जीवन उस आदर्श के निकट दिखाई देता है जिसमें राजा को प्रजा का संरक्षक और धर्म का पालनकर्ता माना गया है। उन्होंने शासन को व्यक्तिगत वैभव का साधन नहीं बनने दिया। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि जब नेतृत्व नैतिकता पर आधारित होता है, तब राष्ट्र सशक्त और समाज संगठित बनता है।

अपने पुत्रों और उत्तराधिकारियों के लिए शिवाजी महाराज केवल दुर्ग, सेना और राज्य नहीं छोड़ गए। उन्होंने उससे कहीं अधिक मूल्यवान विरासत प्रदान की—स्वाभिमान, राष्ट्रनिष्ठा, संगठन, जनसेवा, कर्तव्यपरायणता और सांस्कृतिक गौरव की विरासत। यही कारण है कि उनका प्रभाव उनके जीवनकाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।

आज का भारत यदि शिवाजी महाराज से कोई सबसे बड़ी सीख ग्रहण कर सकता है तो वह है चरित्रवान नेतृत्व की आवश्यकता। आज हमें तकनीक, संसाधन और अवसर तो प्राप्त हैं, किंतु उनके साथ नैतिकता, कर्तव्यबोध और राष्ट्रहित की भावना भी उतनी ही आवश्यक है। शिवाजी महाराज हमें सिखाते हैं कि राष्ट्र का उत्थान केवल आर्थिक प्रगति से नहीं, बल्कि सुदृढ़ चरित्र, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय चेतना से होता है।

विशेष रूप से युवाओं के लिए शिवाजी महाराज का जीवन एक प्रेरणापुंज है। उन्होंने दिखाया कि आयु नहीं, संकल्प महत्वपूर्ण होता है; संसाधन नहीं, लक्ष्य महत्वपूर्ण होता है; परिस्थितियाँ नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। जो युवा अपने भीतर आत्मविश्वास, अनुशासन, राष्ट्रप्रेम और सेवा का भाव विकसित कर लेता है, वह समाज और राष्ट्र के लिए परिवर्तन का माध्यम बन सकता है।

रायगढ़ का राज्याभिषेक इतिहास की एक घटना भर नहीं है। वह भारतीय आत्मा के जागरण का प्रतीक है। वह हमें स्मरण कराता है कि राष्ट्र निर्माण का आधार केवल शक्ति नहीं, बल्कि नीति, नैतिकता, संगठन और लोकमंगल होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन आज भी भारत के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना साढ़े तीन शताब्दी पूर्व था।

उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीता है; जो अधिकार नहीं, कर्तव्य की बात करता है; जो विजय नहीं, न्याय की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाता है। यही छत्रपति शिवाजी महाराज की अमर प्रेरणा है और यही उनके राज्याभिषेक का वास्तविक संदेश भी।

विश्व पर्यावरण दिवस : मुख्यमंत्री साय ने किया एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2026–27 का शुभारंभ

राजीव स्मृति वन में बरगद का पौधा लगाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित राजीव स्मृति वन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2026–27 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कृष्ण वट (बरगद) का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने भी बेल का पौधा लगाकर अभियान में सहभागिता निभाई।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रकृति और मानव जीवन का संबंध अभिन्न है। अनियंत्रित वृक्ष कटाई और पर्यावरणीय असंतुलन पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की दिशा में एक प्रेरक और भावनात्मक पहल है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष प्रदेश में ढाई करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जनसहभागिता और विभागीय प्रयासों

से साढ़े तीन करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस वर्ष भी प्रदेशवासी निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक पौधारोपण कर नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल है जहां लगभग 44 प्रतिशत भू–भाग वनाच्छादित है। राज्य सरकार और वन विभाग के सतत प्रयासों से वन क्षेत्र का संरक्षण और विस्तार निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपने घर, खेत, आंगन और मेड़ों में अपनी माता के नाम एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज की प्रकृति संरक्षण परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जनजातीय समुदाय सदियों से जंगलों को अपनी संस्कृति और जीवन का अभिन्न हिस्सा मानकर उनकी रक्षा करता आया है। सरना स्थलों में वृक्षों को देवतुल्य मानकर पूजा जाना प्रकृति के प्रति हमारी सांस्कृतिक आस्था और संरक्षण की भावना का जीवंत उदाहरण है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समाज सेवा एवं जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पद्मश्री सम्मानित व्यक्तित्व पंडी राम मंडावी, जागेश्वर यादव तथा डॉ. रामचंद्र गोडबोले का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि इन विभूतियों का जीवन समाजसेवा, समर्पण और जनहित का प्रेरणादायी उदाहरण है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों—द बैगा, वेटलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, फ्लोरल डायवर्सिटी ऑफ बीजापुर डिवीजन, ह्यमैमल्स ऑफ छत्तीसगढ़ तथा उत्तरी छत्तीसगढ़ के अनूठे पर्यटन स्थल और उनकी विविधता—का विमोचन भी किया।

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान प्रकृति और मातृत्व के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अनूठा माध्यम है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस अभियान को जन–जन का आंदोलन बनाने का आह्वान किया।

उन्होंने बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को रामसर साइट का दर्जा मिलने पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए इसे छत्तीसगढ़ के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया।

कार्यक्रम में भानुप्रतापपुर विकासखंड के ग्राम सिलीबहार की सुश्री चन्दनबती कोला ने स्व–सहायता समूहों द्वारा जंगल संरक्षण और जैविक खेती के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि गांव में 138 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक एवं जैविक खेती की जा रही है, जिससे युवाओं का पलायन पूरी तरह रुक गया है तथा पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा मिली है।

कार्यक्रम को अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पाण्डेय ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा, आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परम्परा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष अंजय शुक्ला, विधायक मोतीलाल साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

खास खबर

खाद संकट पर कांग्रेस का हमला : दीपक बैज बोले– किसान परेशान, सरकार ट्रेनिंग में व्यस्त

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

कृषि आयुक्त पर भाजपा प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण देने का आरोप, 50% स्टॉक भी नहीं जुटा पाने का दावा

प्रदेश में उर्वरक संकट को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में खाद के लिए मारामारी शुरू हो गई है। किसानों को सोसायटियों में खाद नहीं मिल रहा है।

कृषि आयुक्त पर आरोप : दीपक बैज ने आरोप लगाया कि सरकार खाद की व्यवस्था करने के बजाय भाजपा प्रवक्ताओं को कुतर्क की ट्रेनिंग दे रही है। उन्होंने कहा कि समाचार आया है कि कृषि आयुक्त सीएम हाउस जाकर भाजपा प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग देने गए थे। बैज ने कहा कि कृषि आयुक्त का काम खाद की व्यवस्था बनाना है। उनके पास कोई तथ्य और आंकड़े हों तो मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करें। राजनैतिक प्रशिक्षण देना उनका काम नहीं है।

50% स्टॉक भी नहीं जुटा पाने का दावा : बैज ने कहा कि किसान लगातार मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से उर्वरक के लिए गुहार लगा रहे हैं। सरकार केवल जुबानी आश्वासन दे रही है। इस खरीफ सीजन में 15 लाख 55 हजार मीट्रिक टन खाद की जरूरत है, लेकिन सरकार अभी तक 50 प्रतिशत स्टॉक भी नहीं जुटा पाई है। मानसून आने वाला है। यदि सरकार पर्याप्त उर्वरक नहीं दे पाई तो किसानों के सामने आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा।

पिछले साल का हवाला : उन्होंने कहा कि पिछले खरीफ सीजन में 14 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की जरूरत थी। सरकार शुरुआती दो माह में मात्र 80 हजार मीट्रिक टन ही दे पाई थी। किसान यूरिया, डीएपी और पोटाश के लिए भटकते रहे। बिचौलियों से तीन से चार गुने दाम में खरीदने को मजबूर हुए थे। कांग्रेस ने सरकार से खाद की उपलब्धता पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। प्रेस विज्ञप्ति कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने जारी की।

रील बनाने के लिए अधिकारियों का अपमान बंद करें भाजपा नेता' : कांग्रेस

सुशील आनंद शुक्ला का आरोप, कहा– प्रचार की भूख में कर्मचारियों का सामाजिक उपहास उड़ा रहे

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा नेताओं पर रील बनाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आत्म प्रचार की भूख में भाजपा नेता बिना कारण अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं।

'अलोकतांत्रिक चरित्र' : शुक्ला ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा के मंत्री से लेकर विधायक और छोटे बड़े नेता तक को रील के माध्यम से सस्ता प्रचार पाने की भूख बढ़ गई है। वे अधिकारियों को अपमानित कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं और लानत मलानत भी कर रहे हैं। भाजपाइयों का यह चरित्र अलोकतांत्रिक है।

'शिकायत हो तो विभागीय कार्रवाई करें' : उन्होंने कहा कि शासकीय सेवक जिम्मेदारी से अपना दायित्व निभाते हैं। यदि किसी के काम से शिकायत है तो विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि अभद्र शब्दों और धमकी से अपमानित किया जाए। हर अधिकारी कर्मचारी का अपना सामाजिक सम्मान है। उनके परिवार के सदस्यों का सम्मान भी उनसे जुड़ा है। नेता रील बनाकर अपनी छवि तो चमका रहे हैं, लेकिन कमर्चारी का सामाजिक उपहास उड़ा रहे हैं।

'मनोबल टूट रहा है' : शुक्ला ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री, विधायक, सांसद और भाजपा संगठन के पदाधिकारी तक अधिकारियों को धमकाते हुए रील वायरल कर चुके हैं। इससे अधिकारियों का मनोबल टूट रहा है। सरकार खुद कोई योजना नहीं बना पा रही, दिशा निर्देश जारी नहीं कर पा रही और अपनी कमी छुपाने अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार से इस परंपरा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

समाज, संगठन और योग के प्रति समर्पित था रूपनारायण सिन्हा का जीवन : मुख्यमंत्री साय

छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष स्व. रूपनारायण सिन्हा को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष स्वर्गीय रूपनारायण सिन्हा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिन्हा का संपूर्ण जीवन समाजसेवा, संगठन निर्माण और योग के प्रचार–प्रसार के लिए समर्पित रहा। उनका निधन न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय रूपनारायण सिन्हा एक कुशल संगठनकर्ता, सरल, सौम्य और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपने व्यवहार, कार्यशैली और समर्पण से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विशेष पहचान बनाई थी। योग के प्रति उनकी निष्ठा और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें विशिष्ट बनाती थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद श्री सिन्हा ने पूरे समर्पण और ऊर्जा के साथ योग आंदोलन को नई दिशा देने का कार्य किया। उन्होंने योग को केवल स्वास्थ्य का माध्यम नहीं, बल्कि जीवनशैली का हिस्सा बनाने के लिए अनेक नवाचार किए। उनके प्रयासों से प्रदेश में योग गतिविधियों को नई पहचान और व्यापक जनस्वीकृति मिली।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वर्गीय श्री सिन्हा के साथ बिताए गए क्षणों को स्मरण करते हुए कहा कि उनसे नियमित मुलाकात होती थी और हर मुलाकात में वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए योग आधारित नए विचार साझा करते थे। उनकी सोच सदैव रचनात्मक और जनहितकारी होती थी। वे योग को जन–जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर सक्रिय रहते थे और इसी उद्देश्य को अपने जीवन का मिशन बना चुके थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष जशपुर के रणजीता स्टेडियम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की सफलता में श्री सिन्हा की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। सीमित समय में उन्होंने जिस कुशलता और प्रतिबद्धता के साथ उस आयोजन को भव्य स्वरूप दिया, वह उनकी संगठन क्षमता और कार्यकुशलता कावो उत्कृष्ट उदाहरण है। उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता ने योग के प्रति जनजागरूकता को नई ऊंचाई प्रदान की थी। उनका जीवन समाज के प्रति समर्पण, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक था, जो आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा देता रहेगा।

मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

श्रद्धांजलि सभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, वन मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, विधायक अमर अग्रवाल, विधायक धरमलाल कौशिक, विधायक अजय चंद्राकर, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, रमेश बैस, राम प्रताप, पवन साय, डॉ. पूर्णेन्दु सक्सेना, राम दत्त, राजीव लोचन महाराज सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, योग साधक एवं योग जगत से जुड़े लोगों ने उपस्थित होकर स्वर्गीय रूपनारायण सिन्हा को श्रद्धासुमन अर्पित किया।

शिक्षा के साथ कौशल विकास से बढ़ता है आत्मविश्वास : अरुण

लोरमी में 250 युवाओं को कंप्यूटर, सिलाई और ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण, उप मुख्यमंत्री ने किया संवाद

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी में कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने युवाओं को जीवन में निरंतर आगे बढ़ने और अपने कौशल को लगातार विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र में संचालित गतिविधियों का अवलोकन कर प्रशिक्षणार्थियों के अनुभव भी सुने।

उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुरूप निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एसईसीएल के सहयोग से 1 अप्रैल से 250 युवा कंप्यूटर, सिलाई एवं ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। युवाओं में नए कौशल सीखने को लेकर उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है, जो उनके उज्ज्वल भविष्य की सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत करता है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि, आज के समय में शैक्षणिक योग्यता ही पर्याप्त नहीं है। पढ़ाई के साथ किसी एक व्यावहारिक कौशल का होना भी अत्यंत आवश्यक है। ब्यूटीशियन, सिलाई, डाटा एंट्री जैसे प्रशिक्षण युवाओं को अतिरिक्त दक्षता प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि, कौशल विकास युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उनके व्यक्तित्व को भी सशक्त बनाता है।

श्री साव ने युवाओं से कहा कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भी सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकनी चाहिए। निरंतर अभ्यास और सीखने की प्रवृत्ति ही सफलता का आधार है। उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त कौशल होता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह हर परिस्थिति में सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सक्षम बनता है। यही आत्मविश्वास जीवन में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी शक्ति है जो सफलता की नई राहें खोलता है।

सुशासन तिहार : मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सुनीं 17 गांवों की समस्याएं, त्वरित निराकरण के निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल सुशासन तिहार 2026 के तहत सूरजपुर जिला के भैयाथान विकासखंड के चंद्रमेढ़ा में आयोजित समाधान शिविर में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को सभी आवेदनों का समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

चंद्रमेढ़ा हाईस्कूल मैदान में आयोजित शिविर में 17 ग्रामों के ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। शिविर में सुशासन तिहार के तहत पहले प्राप्त 629 आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की गई, जिनमें 612 मांगों और 17 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। वहीं शिविर के दौरान 328 नए आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें संबंधित विभागों को कार्रवाई

के लिए सौंपा गया।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन का गुणवत्तापूर्ण निराकरण कर इसकी जानकारी आवेदकों तक भी पहुंचाई जाए।

शिविर में जनकल्याणकारी गतिविधियों के तहत 100 पौधों का वितरण किया गया। पात्र हितग्राहियों को 4 नए राशन कार्ड प्रदान किए गए, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 8 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और 8 शिशुओं का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराया गया।

इस अवसर पर स्वास्थ्य, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, खाद्य तथा महिला एवं बाल विकास विभागों के स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ, जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी–कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

विश्व पर्यावरण दिवस मंत्री राजवाड़े ने किया पौधरोपण

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सूरजपुर जिले के भटगांव नगर पंचायत स्थित पुष्प वाटिका में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आम एवं अमरूद के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से प्रकृति के संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण संतुलन का आधार नहीं हैं, बल्कि मानव जीवन, स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के संरक्षक भी हैं। उन्होंने कहा कि आज जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण की चुनौतियों के बीच प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसके संरक्षण का संकल्प भी ले।

चतुर्थ दीक्षांत समारोह : 9 हजार 194 विद्यार्थियों को दी गई उपाधि

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा है कि डिजिटल एडिक्शन आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बनती जा रही है। यह केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। नई पीढ़ी को डिजिटल एडिक्शन और पॉपकॉर्न मेंटल स्टेटस से बाहर निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे सोचने–समझने की क्षमता प्रभावित होती है और केवल कृत्रिम संतुष्टि प्राप्त होती है।

राज्यपाल रमेन डेका ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के अध्यक्षीय उद्बोधन में उक्त बातें कही। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समारोह में मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, मेडिकल बायोटेक, बीपीपी, एमपीटी, नर्सिंग, बीएएसएलपी सहित अन्य संकायों में 7545 स्नातक और 1645 स्नातकोत्तर एवं 5 सुपर स्पेशयलिटी उपाधि प्रदान की गई तथा विभिन्न संकायों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न

स्वर्ण पदक प्रदान किए गए।

श्री डेका ने कहा कि वर्तमान समय में नेबरहुड डॉक्टरों की सबसे अधिक आवश्यकता है। पहले फैमिली फिजिशियन की परंपरा थी, जो मरीज और उसके परिवार की परिस्थितियों को भलीभांति समझते थे। चिकित्सा क्षेत्र में उस आत्मीयता को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। किसी भी मरीज के लिए गोल्डन ऑवर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समय में चिकित्सकों की त्वरित निर्णय क्षमता मरीज का जीवन बचा सकती है। राज्यपाल ने कहा कि आज के छात्र इंटरनेट युग के विद्यार्थी हैं। विज्ञान निरंतर आगे बढ़ रहा है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) चिकित्सा क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही है। टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकों का उपयोग दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आज का दिन केवल उपाधि प्राप्त करने का अवसर नहीं है बल्कि समाज और मानवता के प्रति नई दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लेने का अवसर है। विद्यार्थियों की सफलता उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ–साथ छत्तीसगढ़ के प्रगति और विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा को दर्शाता है। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ केवल खनिज और कृषि आधारित राज्य के रूप में ही नहीं बल्कि ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित करें यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करना लोगों की सेवा का बड़ा अवसर और महती जिम्मेदारी है। उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विस्तृत जानकारी दी। अध्यक्ष, राष्ट्रीय विशेषज्ञ पैनल, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नई दिल्ली एवं दीक्षांत समारोह अभिभाषक डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा ने भी अपना संबोधन दिया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. पी. के. पात्रा ने स्वागत उद्बोधन एवं अकादमिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा सहित विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद के सदस्य, अधिष्ठाता, प्राध्यापकगण, विद्यार्थी एवं अभिभावक उपस्थित थे।

निजी स्कूलों को किताबों के लिए 200 किमी का सफर, एसोसिएशन ने जताई नाराजगी

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सचिव को लिखा पत्र, कहा– सरकारी स्कूलों को घर बैठे किताबें, हमसे सौतेला व्यवहार

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सचिव स्कूल शिक्षा को पत्र लिखकर निजी स्कूलों के लिए किताबें समय पर उपलब्ध कराने का निवेदन किया है। एसोसिएशन ने पाठ्य पुस्तक निगम पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।

16 जून से खुलेंगे स्कूल

ज्ञात हो कि सभी स्कूल 16 जून से ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद दोबारा खुलेंगे। एसोसिएशन का कहना है कि पाठ्य पुस्तक निगम ने सरकारी स्कूलों के लिए किताबों की सप्लाई शुरू कर दी है। लेकिन निजी स्कूलों के लिए अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है।

सौतेला व्यवहार का आरोप

एसोसिएशन ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग निजी स्कूलों से सौतेला व्यवहार कर रहा है। सरकारी स्कूलों को संकुल स्तर पर किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं निजी स्कूलों को पाठ्यपुस्तक निगम के डिपो से किताबें लेनी पड़ेंगी। इसके लिए स्कूलों को 150 से 200 किलोमीटर की दूरी तय कर जाना पड़ेगा।

एसोसिएशन ने मांग की है कि निजी स्कूलों को भी संकुल स्तर पर या जिले में किताबें उपलब्ध कराई जाएं ताकि समय पर सत्र शुरू हो सके।

संपादकीय

चुनाव जिता नहीं पाते हैं इसलिए सपने देखते हैं

हर क्षेत्र में दो तरह के लोग होते हैं एक जो सपना देखते हैं और उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं,निरंतर प्रयास में जुटे रहते हैं और एक दिन अपना सपना पूरा कर लेते हैं। एक होते हैं जो सपने तो देखते हैं लेकिन उनको यही पता नहीं रहता है कि सपने को पूरा कैसे किया जाता है। उनका एक सपना पूरा नहीं होता है तो दूसरा सपना देखते हैं, दूसरा पूरा नहीं होता है तो तीसरा सपना देखते हैं और निरंतर सपना देखते रहते हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी इसी तरह के आदमी हैं। वह सपने तो देखते रहते हैं लेकिन सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको यही पता नहीं है कि उनका सपना कैसे पूरा हो सकता है। किसी सपने को पूरा करने के लिए दस बारह साल बहुत होते हैं कोई भी आदमी दस बारह साल किसी सपने को पूरा करने का प्रयास करे तो वह सफल हो सकता है लेकिन राहुल गांधी दस बारह साल से अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

राहुल गांधी का एक ही सपना है कि पीएम मोदी को हराना और वह पीएम मोदी को तीन चुनाव हो गए हरा नहीं पा रहे हैं। खुद हरा नहीं पा रहे हैं इसलिए वह सपना देखते रहते हैं कि छह माह में मोदी सरकार गिर जाएगी, मोदी सरकार कमजोर सरकार इसलिए वह ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। मोदी सरकार तो दो बैसाखी पर टिकी सरकार है किसी भी दिन गिर जाएगी। राहुल गांधी बारह साल हो गए कहते रहते हैं लेकिन उनके कहे अनुसार तो कुछ नहीं होते है। देश के लोगों को आदत हो गई है, सुनने की कि राहुल गांधी तो कुछ भी कहते रहते हैं और वह जैसा कहते हैं वैसा तो बिलकुल नहीं होता है।अब राहुल गांधी ने कहा है कि चीजों को नियंत्रित करने का सिस्टम अब ध्वस्त हो रहा है और उनका अंदाजा है कि एक साल के भीतर पीएम मोदी पद पर नहीं रहेंगे। एक कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया है कि अब सरकार के भीतर से ही संस्थागत विद्रोह शुरू हो गया है और बहुत बड़ी आर्थिक सुनामी आने वाली है क्योंकि इस सरकार ने अर्थव्यस्था को सुरक्षित करने वाले कवच को ही नष्ट कर दिया है। राहुल गांधी कह रहे है कि अब मुझे चुनाव आयुक्त के संदेश आ रहे है,खुफिया सिस्टम के प्रमुख के संदेश आ रहे हैं,उच्च न्यायपालिका के लोगों की तरफ से विद्रोह हो रहा है।

यह भी राहुल गांधी का सपना है क्योंकि वह एक चुनाव नहीं जिता पा रहे है इसलिए हताशा व निराशा में सपने देख रहे हैं,कुछ तो ऐसा होगा जिससे मोदी को सत्ता छोड़ना पड़ेगा। कभी चंद्रबाबू नायडू से उम्मीद करते हैं कि वह सरकार गिरा देंगे कभी नीतीश कुमार से उम्मीद करते हैं कि वह सरकार गिरा देंगे। ऐसा हुआ नही तो अब वह उम्मीद कर रहे हैं कि देश में आर्थिक सुनामी आएगा तो मोदी सरकार चली जाएगी। अब तक जिन संस्थाओं को राहुल गांधी कम्प्रोमाइज्सड कहते थे, अब वह देख रहे है और देश को बता रहे हैं कि वह सारी संस्थाएं जो पिछले महीने तक कंप्रोमाइज्ड थी, वह अब विद्रोह करने जा रही है और वह सब राहुल गांधी को संदेश भेज कर यह बता रहे हैं। राहुल गांधी खुद कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके पास सबसे पुरानी पार्टी और विपक्ष भी उनके साथ है कि पीएम मोदी को हराना है लेकिन यही काम राहुल गांधी कर नहीं पा रहे हैं ।क्योंकि लोगों को लगता है कि राहुल गांधी देश के विकास के लिए, देश के भले के लिए कुछ सोच नहीं रहे हैं, उनको मालूम है कि आर्थिक सुनामी आने वाली है जनता को बहुत तकलीफ होगी लेकिन वह बता नहीं रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए जिससे जनता को तकलीफ न हो, वह तो जनता को तकलीफ होने का इंतजार कर रहे हैं। वह सोचते हैं कि जनता को तकलीफ होगी तो जनता सड़क पर आएगी और पीएम मोदी को सत्ता से हटा देगी।

वह तो कोरोना के वक्त भी ऐसा सोच रहे थे, वह किसान आंदोलन के समय भी ऐसा सोच रहे थे, वह तो बांग्लादेश, नेपाल में जेनजी के आंदोलन के समय ऐसा सोच रहे थे कि भारत में भी ऐसा आंदोलन होगा और सत्ता कांग्रेस को मिल जाएगी। कई दिनों तक जेन जी को जगाने, आंदोलन करने,सड़क पर उतरने की अपेक्षा की जाती रही लेकिन कई माह बाद भी जेनजी भारत में सड़क पर नहीं उतरा है तो अब एक नया आंदोलन शुरू करने की तैयारी की जा रही है. यह आंदोलन काकरोच जनता पार्टी करने वाली है। वह भी जनता के गुस्से को भुनाने के लिए उकसाने व भड़काने वाली बातें कर रही है और राहुल गांधी सहित विपक्ष उम्मीद कर रहे हैं काकरोच जनता पार्टी जरूर देश के युवाओं को सड़क पर लाएगी और ऐसा बड़ा आंदोलन होगा कि मोदी सरकार को जाना पड़ेगा। राहुल गांधी और विपक्ष अब तक कुछ कर नहीं पाया है इसलिए उनको लगता है कि जेनजी कुछ करेगा, काकरोच जनता पार्टी कुछ करेगी। देश की जनता सब समझती है कि इस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए विदेशी ताकते पिछले 12 सालों में कैसा कैसा खेल खेलती आई है और राहुल गांधी सहित विपक्ष कैसे उनके हाथ का खिलौना बन जाता है।.यही वजह है कि जनता मोदी के साथ खड़ी रहती है और उनको जब भी चुनाव में मौका आता है तो हर तरह से मजबूत करती है।

यह सच है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी होता है लेकिन हमारे देश का विपक्ष तो लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पर लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करता रहा है, यही वजह है जब भी जनता को चुनाव में मौका मिला है तो जनता ने ज्यादातर राज्यों के चुनाव में विपक्ष को हराने काम किया है, विपक्ष को कमजोर कर पीएम मोदी को और मजबूत करने का काम किया है। विपक्ष तमिलनाडु व पं.बंगाल मे सबसे मजबूत था जनता ने दोनों जगह विपक्ष के दो मजबूत नेताओं को चुनाव में हराकर साफ कर दिया है कि देश के खिलाफ सोचने वालों के साथ वह नहीं है। जो देश के लिए बुरा सोचते रहते हैं,जनता उनके साथ नहीं है। दो राज्यों में विपक्ष की हार से विपक्ष कमजोर हुआ है तो उसके लिए राहुल गांधी सहित विपक्ष के तमाम नेता दोषी है क्योंकि वह कभी यह सोच नहीं पाते हैं, कहते नहीं है कि वह देश के लिए मोदी से बेहतर क्या करने वाले हैं। वह कहते हैं कि मोदी को गद्दी से हटा दो सब ठीक हो जाएगा, जनता इस बात पर यकीन नहीं करती है।

विश्व पर्यावरण दिवस : विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की नई चुनौती

विनय कुमार सिंह

विश्व पर्यावरण दिवस 2026 ऐसे समय में मनाया जा रहा है जब मानव सभ्यता विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने की ऐतिहासिक चुनौती का सामना कर रही है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाने वाला यह दिवस केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर नहीं है, बल्कि यह आत्ममंथन का भी अवसर है कि हमारी विकास यात्रा किस दिशा में आगे बढ़ रही है। बीते कुछ दशकों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, औद्योगीकरण और वैश्वीकरण ने मानव जीवन को अभूतपूर्व सुविधाएँ प्रदान की हैं। जीवन स्तर में सुधार हुआ है, संचार और परिवहन के साधन विकसित हुए हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं तथा आर्थिक विकास ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की है। किंतु इस विकास की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, वनों की कटाई, प्रदूषण, जैव विविधता का ह्रास, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति इस बात का संकेत हैं कि विकास की वर्तमान प्रक्रिया पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ नहीं है। ऐसे में विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह हमें विकास की अवधारणा को पुनर्परिभाषित करने और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता की याद दिलाता है।

21वीं सदी को विकास, तकनीक और नवाचार की सदी कहा जाता है, लेकिन यह पर्यावरणीय संकट की सदी भी बनती जा रही है। पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम चक्र अनिश्चित होते जा रहे हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी, बाढ़, सूखा, चक्रवात और जंगलों में आग जैसी घटनाएँ अधिक तीव्रता और आवृत्ति के साथ सामने आ रही हैं। हिमालयी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और अनेक द्वीपीय क्षेत्रों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पर्यावरणीय संकट का यह स्वरूप केवल प्रकृति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक स्थिरता को भी प्रभावित कर रहा है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि पर्यावरणीय समस्याएँ अब केवल वैज्ञानिक या पारिस्थितिक विषय नहीं रह गई हैं, बल्कि वे मानव विकास की केंद्रीय चुनौतियों में परिवर्तित हो चुकी हैं।

विकास और पर्यावरण के बीच संघर्ष का प्रश्न नया नहीं है। औद्योगिक क्रांति के बाद से आर्थिक विकास को राष्ट्रों की प्रगति का प्रमुख आधार माना गया। अधिक उत्पादन, अधिक उपभोग और अधिक आर्थिक वृद्धि को विकास का पर्याय समझा गया। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को सफलता का प्रमुख मापदंड बनाया गया। परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की गति बढ़ती गई। वन क्षेत्रों को उद्योगों और शहरों के विस्तार के लिए परिवर्तित किया गया, नदियों को प्रदूषित किया गया, खनिज संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया गया और ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ी। इन गतिविधियों ने आर्थिक प्रगति को तो गति दी, लेकिन पर्यावरणीय संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। आज यह स्पष्ट हो चुका है कि केवल आर्थिक वृद्धि को विकास का आधार मानना पर्याप्त नहीं है। यदि विकास भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता को कम कर देता है, तो वह विकास नहीं बल्कि विनाश का मार्ग बन जाता है।

जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौती है। इसके प्रभाव विश्व के लगभग प्रत्येक देश में अनुभव किए जा रहे हैं। बढ़ते तापमान के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। अनियमित वर्षा और जल संकट किसानों की आजीविका को प्रभावित कर रहे हैं। समुद्र स्तर में वृद्धि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए चिंता का विषय है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इसके गंभीर प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। वायु प्रदूषण, तापजनित बीमारियाँ और जलजनित रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव उन समुदायों पर पड़ता है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर हैं। यही कारण है कि आज पर्यावरणीय संकट को सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के प्रश्न से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

भारत के संदर्भ में यह चुनौती और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत एक विकासशील राष्ट्र है जहाँ आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन अभी भी प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं। साथ ही भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। देश के कई हिस्से जल संकट, भूमि क्षरण और प्रदूषण जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। दिल्ली सहित अनेक महानगरों में वायु प्रदूषण गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों का पिघलना और चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। इसलिए भारत के लिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना केवल एक नीति विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता है।

सतत विकास की अवधारणा इसी चुनौती का समाधान प्रस्तुत करती है। सतत विकास का अर्थ है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करना कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता प्रभावित न हो। यह अवधारणा आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने पर बल देती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य इसी सोच का वैश्विक स्वरूप हैं। गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ जल, लैंगिक समानता, जलवायु कार्रवाई और सतत उपभोग जैसे लक्ष्य यह स्पष्ट करते हैं कि विकास को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है।

वर्तमान समय में हरित अर्थव्यवस्था सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रही है। हरित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक विकास को पर्यावरणीय क्षति से अलग करना है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, हरित उद्योग, जैविक कृषि और परिपत्र अर्थव्यवस्था जैसे तत्व शामिल हैं। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे स्रोत ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देते हैं। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि हरित अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से अपनाया जाए तो आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को एक साथ आगे बढ़ाया जा सकता है।

तकनीक सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भू-स्थानिक तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा जैसी आधुनिक तकनीकें पर्यावरणीय प्रबंधन को अधिक प्रभावी बना रही हैं। जल संसाधनों का प्रबंधन, आपदा पूर्वानुमान, प्रदूषण नियंत्रण और कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए तकनीकी नवाचार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हालाँकि यह भी आवश्यक है कि तकनीकी विकास मानव और प्रकृति दोनों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाए। केवल तकनीक पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा; इसके साथ नैतिकता और उत्तरदायित्व का समावेश भी आवश्यक है।

पर्यावरणीय संकट के समाधान में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा केवल जानकारी प्रदान करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यवहार परिवर्तन का साधन भी है। पर्यावरणीय जागरूकता तभी प्रभावी होगी जब वह लोगों के जीवन का हिस्सा बने। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी पर्यावरणीय शिक्षा और सतत विकास को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। यदि युवा पीढ़ी पर्यावरणीय मूल्यों को आत्मसात कर लेती है, तो भविष्य में अधिक जिम्मेदार और जागरूक समाज का निर्माण संभव होगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में अत्यंत समृद्ध और प्रासंगिक है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार माना गया है। पृथ्वी को माता, नदियों को देवी और वृक्षों को जीवनदाता के रूप में सम्मान दिया गया है। वेदों और उपनिषदों में प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन का संदेश मिलता है। "वसुधैव कुटुम्बकम्" की अवधारणा संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की प्रेरणा देती है। आज जब विश्व पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहा है, तब भारतीय ज्ञान परंपरा के ये मूल्य सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।

पर्यावरणीय न्याय की अवधारणा भी वर्तमान समय में विशेष महत्व रखती है। पर्यावरणीय संकट का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से नहीं पड़ता। गरीब, आदिवासी, किसान और हाशिए पर स्थित समुदाय इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव झेलते हैं। विकास की नीतियाँ तभी न्यायसंगत मानी जाएँगी जब वे इन वर्गों के हितों की रक्षा करें और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान करें। इसलिए सतत विकास का अर्थ केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि सामाजिक समानता और न्याय सुनिश्चित करना भी है।

विश्व पर्यावरण दिवस 2026 हमें यह संदेश देता है कि विकास और पर्यावरण को प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। वास्तविक विकास वही है जो आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक कल्याण और पर्यावरणीय संतुलन सुनिश्चित करे। आज आवश्यकता ऐसी नीतियों, तकनीकों और जीवनशैलियों की है जो पृथ्वी के सीमित संसाधनों का सम्मान करें और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करें। सरकारों, उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज को मिलकर कार्य करना होगा ताकि सतत विकास केवल एक नारा न रह जाए, बल्कि व्यवहारिक वास्तविकता बन सके।

अंततः यह समझना आवश्यक है कि पृथ्वी केवल वर्तमान पीढ़ी की संपत्ति नहीं है। यह आने वाली पीढ़ियों की भी धरोहर है। यदि हम आज प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करने में सफल होते हैं, तो हम एक सुरक्षित, समृद्ध और हरित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 हमें इसी दिशा में सोचने, कार्य करने और सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देता है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की यह नई चुनौती वास्तव में मानव सभ्यता के भविष्य को सुरक्षित बनाने का अवसर भी है। यही इस दिवस का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है और यही सतत विकास की वास्तविक आधारशिला भी।

(लेखक : माँ गौरी समग्र एवं परिवर्तनकारी शिक्षा संस्थान और तेजस आईएएस अकादमी के निदेशक हैं।)

गर्म समुद्र नाराज हो गया है : अब सुपर एल नीनो हमें भविष्य का आईना दिखाएगा

नितिन सिंघवी

प्रकृति हमें बार-बार चेतावनी देती रही कि संभल जाओ, परन्तु हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ाते रहे, जिससे समुद्र भी गर्म हो गए। तूफान, हीटवेव और चरम मौसमी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उत्सर्जन इसी तरह जारी रहा तो आने वाले दशक मानव इतिहास के सबसे खतरनाक जलवायु वर्षों में बदल सकते हैं।

अब पूरी दुनिया की नजर 2026-2027 के सुपर एल नीनो पर है। ऐसा ही एक शक्तिशाली एल नीनो 1876-78 में आया था, जिसमें दक्षिण और मध्य भारत के बड़े हिस्से प्रभावित हुए थे। फसलें नष्ट हुईं, पानी का संकट बढ़ा और लाखों लोग भूख व बीमारियों से मारे गए, जबकि दुनिया भर में करोड़ों लोग प्रभावित हुए। आज विश्व की आबादी पहले से कहीं अधिक है। ऐसे में 2026-2027 का सुपर एल नीनो हमें भविष्य का वह आईना दिखा सकता है, जिसमें पृथ्वी अधिक गर्म, अधिक अस्थिर और अधिक खतरनाक दिखाई देगी। यह हमें अधिक तापमान वाली एक नई दुनिया की ओर ले जा सकता है।

एल नीनो और ला नीना प्रशांत महासागर में कुछ वर्षों के अंतराल पर होने वाले दो विपरीत मौसमीय बदलाव हैं। जब प्रशांत महासागर का मध्य और पूर्वी भाग सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है तो उसे एल नीनो कहा जाता है, जिससे दुनिया का तापमान और मौसम प्रभावित होता है। इसके विपरीत जब वही क्षेत्र सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है तो उसे ला नीना कहा जाता है। एल नीनो आमतौर पर वैश्विक गर्मी बढ़ाता है, जबकि ला नीना कुछ समय के लिए उसे थोड़ा कम करती है।

लेकिन अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही। पहले एल नीनो एक प्राकृतिक घटना माना जाता था, पर अब जलवायु परिवर्तन ने इसे अधिक खतरनाक बना दिया है। समुद्र पहले से ही रिकॉर्ड स्तर तक गर्म हैं। वैज्ञानिक जेम्स हैनसेन सहित कई वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि जल्दी ही पृथ्वी का तापमान औद्योगिक युग की तुलना में 1.5त्ज से ऊपर जाएगा और बाद के वर्षों में 2.0त्ज से ऊपर पहुँच सकता है। हैनसेन के अनुसार 2027 में पृथ्वी अस्थायी रूप से लगभग 1.7त्ज तक की गर्मी महसूस कर सकती है। यह दुनिया को भविष्य की उस जलवायु की झलक दिखा सकता है, जहाँ अत्यधिक गर्मी, बाढ़, कम वर्षा, सूखा और मौसमीय अव्यवस्था सामान्य बात हो जाएगी। विश्व स्तर पर सूखा, बाढ़, जंगल की आग, हीटवेव और खाद्य संकट बढ़ सकते हैं। समुद्र का बढ़ता तापमान तूफानों और चक्रवातों को अधिक ऊर्जा देगा। गर्म समुद्र ज्यादा बादल बनाते हैं और गर्म वातावरण अधिक जलवाष्प रोकता है, जिससे कम समय में अत्यधिक वर्षा और विनाशकारी बाढ़ की घटनाएँ बढ़ सकती हैं।

भारत पर इसका प्रभाव सबसे गंभीर रूप में महसूस किया जाएगा क्योंकि यहाँ बड़ी आबादी मानसून और कृषि पर निर्भर है। उत्तर-पश्चिम भारत जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में अत्यधिक हीटवेव और पानी का संकट बढ़ सकता है। पूर्वी और मध्य भारत में हीटवेव के अलावा सूखा, तेज आंधी, असामान्य वर्षा और बिजली गिरने की घटनाएँ बढ़ सकती हैं। हिमालयी राज्यों में भूस्खलन, बादल फटने और ग्लेशियर लेक फटने की घटनाएँ तेज हो सकती हैं। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गर्मी और चक्रवातों की तीव्रता बढ़ सकती है। दक्षिण भारत में मानसून की अनियमितता, अत्यधिक वर्षा और शहरी बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है।

कंक्रीट, कम पेड़, बढ़ती जनसंख्या और एयर-कंडीशनर आधारित जीवनशैली ने शहरों को ह्लहीट ट्रैपह्व बना कर नया संकट पैदा कर दिया है। बिजली की मांग बढ़ेगी, पानी का संकट बढ़ेगा, आंधी तूफान से और लंबे पावर कट आम लोगों को भारी परेशानी में डाल सकते हैं। अधिक आद्रर्ता और लंबी गर्मी अधिक मच्छर पैदा करेगी जिससे बीमारियाँ बढ़ेंगी। गर्म और उमस भरे मौसम में गरीब, मजदूर, किसान और झुग्गी क्षेत्रों में रहने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित होंगे।

ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप आते हैं, जंगल जलते हैं और प्रकृति समय के साथ खुद को संभाल लेती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन अलग है। यह प्रकृति का काम नहीं, बल्कि मानव गतिविधियों का परिणाम है। इस बार इंसान ने स्वयं पृथ्वी को चोट पहुँचाई है और उसे ऐसी स्थिति में पहुँचा दिया है, जहाँ वह मानो चट्टान की चोटी पर खड़ी हो — अब गिरी कि तब गिरी।

अब यदि अचानक कार्बन उत्सर्जन पूरी तरह बंद भी कर दिया जाए, तब भी तापमान बढ़ता रहेगा, क्योंकि गर्म और नाराज समुद्र अपने भीतर सोखी हुई गर्मी को लंबे समय तक छोड़ते रहेंगे और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी लंबे समय तक बनी रहेगी। अब समय रहते हमें तकलीफों के साथ जीना सीखना पड़ेगा। आने वाले वर्षों में बार-बार आने वाले सुपर एल नीनो जलवायु संकट के साथ मानव सभ्यता के लिए बड़ी चेतावनी बन सकते हैं।

विश्व पर्यावरण दिवस : तकनीकी नवाचार से सशक्त हो रहा पर्यावरण संरक्षण

धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक जनसंपर्क, सुनील त्रिपाठी, सहायक संचालक, जनसंपर्क, रायपुर

धरती केवल हमारे रहने का स्थान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर है। स्वच्छ हवा, निर्मल जल, हरे-भरे वन और समृद्ध जैव विविधता ही मानव सभ्यता के अस्तित्व का आधार हैं। लेकिन आज जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन ने पूरी दुनिया के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विकास की दौड़ में प्रकृति की अनदेखी अंतत : मानव जीवन के लिए ही खतरा बन सकती है। इसलिए आज आवश्यकता ऐसी विकास नीति की है जो समृद्धि के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी सुरक्षित रखे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार इसी संतुलित विकास की अवधारणा को आगे बढ़ा रही है। राज्य में पर्यावरणीय शासन को आधुनिक तकनीकों से जोड़ते हुए प्रदूषण नियंत्रण, संसाधन संरक्षण और सतत विकास की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

पर्यावरण संरक्षण में तकनीकी क्रांति: ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली : 21वीं सदी में तकनीक केवल सुविधा का माध्यम नहीं, बल्कि सुशासन और संसाधन संरक्षण का प्रभावी उपकरण बन चुकी है। पर्यावरणीय निगरानी के क्षेत्र में ड्रोन आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम इसी परिवर्तन का प्रतीक है। पहले जिन क्षेत्रों तक पहुँचना कठिन था, जहाँ प्रदूषण के स्रोतों की सटीक पहचान में समय लगता था, वहाँ अब अत्याधुनिक सेंसरों से लैस ड्रोन कुछ ही मिनटों में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं।

ड्रोन तकनीक के माध्यम से : ड्रोन तकनीक के माध्यम से PM2.5 एवं PM10 जैसे सूक्ष्म कणों की निगरानी, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों का विश्लेषण, औद्योगिक चिमनियों से निकलने वाले उत्सर्जन की ऊँचाई पर निगरानी, नदियों एवं जलाशयों की जल गुणवत्ता का परीक्षण, अवैध अपशिष्ट निस्तारण की पहचान तथा प्रदूषण प्रभावित हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सटीक मैपिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावी ढंग से किए जा रहे हैं। इससे प्रदूषण स्रोतों की शीघ्र पहचान, वैज्ञानिक विश्लेषण तथा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई संभव हो रही है।

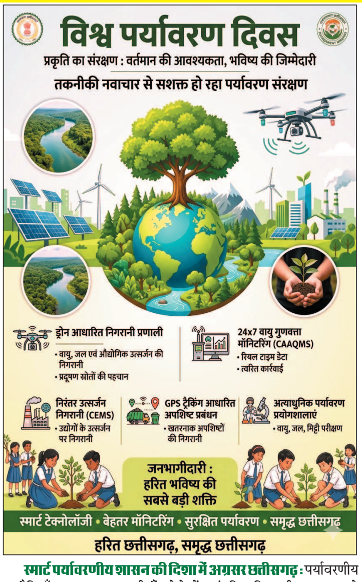

स्मार्ट पर्यावरणीय शासन की दिशा में अग्रसर छत्तीसगढ़ : पर्यावरणीय चुनौतियाँ लगातार बदल रही हैं। ऐसे में पारंपरिक निगरानी व्यवस्था को आधुनिक तकनीकों से सशक्त बनाना समय की मांग है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी दृष्टिकोण के साथ तकनीक आधारित पर्यावरणीय शासन को प्राथमिकता दी है।

24 घंटे वायु गुणवत्ता पर निगरानी : राज्य में कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम (उअअदटर) का विस्तार किया जा रहा है। यह प्रणाली चौबीसों घंटे वायु की गुणवत्ता का विश्लेषण कर वास्तविक समय में आंकड़े उपलब्ध कराती है। इससे प्रदूषण की स्थिति का वैज्ञानिक आकलन संभव हो रहा है तथा नागरिकों को भी वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी प्राप्त हो रही है।

उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण को मिली नई मजबूती : औद्योगिक विकास राज्य की आर्थिक प्रगति का आधार है, लेकिन यह पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी उद्देश्य से उद्योगों में कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है। यह प्रणाली उद्योगों के उत्सर्जन की निरंतर निगरानी करती है और किसी भी मानक उल्लंघन की स्थिति में तत्काल जानकारी उपलब्ध कराती है। इससे प्रदूषण नियंत्रण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनी है।

GPS ट्रैकिंग से खतरनाक अपशिष्टों पर नियंत्रण : औद्योगिक अपशिष्टों का वैज्ञानिक प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण की महत्वपूर्ण कड़ी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने खतरनाक अपशिष्टों के परिवहन एवं निपटान की निगरानी के लिए ॠढर आधारित ट्रैकिंग प्रणाली लागू की है। इस व्यवस्था से अपशिष्ट के उत्पन्न होने से लेकर उसके अंतिम निस्तारण तक की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध रहती है। इससे अवैध डंपिंग और पर्यावरणीय क्षति की संभावनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है।

अत्याधुनिक पर्यावरण प्रयोगशालाएँ : वैज्ञानिक निणर्यों का आधार : सटीक आंकड़े और वैज्ञानिक विश्लेषण किसी भी प्रभावी पर्यावरणीय नीति की आधारशिला होते हैं। राज्य में स्थापित अत्याधुनिक केंद्रीय पर्यावरण प्रयोगशाला वायु, जल, मिट्टी और अपशिष्ट नमूनों का उच्च स्तरीय परीक्षण कर रही है। इसके अतिरिक्त मोबाइल पर्यावरण प्रयोगशालाएँ भी आकस्मिक निरीक्षण और त्वरित परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन सुविधाओं के माध्यम से प्रदूषण की घटनाओं का शीघ्र पता लगाया जा सकता है और आवश्यक कार्रवाई समय पर सुनिश्चित की जा सकती है।

पर्यावरण संरक्षण और उद्योगों के बीच संतुलन : प्रदेश सरकार ने पर्यावरणीय मानकों से समझौता किए बिना उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया है। स्थापना अनुमति और संचालन अनुमति की प्रक्रियाओं को समयबद्ध एवं डिजिटल बनाया गया है। अनेक श्रेणियों में स्व-प्रमाणन आधारित नवीनीकरण की सुविधा प्रदान कर उद्योगों को राहत दी गई है। यह पहल इस बात का उदाहरण है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं।

जनभागीदारी: हरित भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति : पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है। यह तब सफल होगा जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी को समझे और निभाए। इसी उद्देश्य से राज्य में ईको-क्लब कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों के हजारों विद्यार्थी वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त अभियान, स्वच्छता कार्यक्रम तथा जैव विविधता संरक्षण गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। युवा पीढ़ी में पर्यावरणीय चेतना का विकास भविष्य के हरित भारत की मजबूत नींव तैयार कर रहा है।

भविष्य की दृष्टि 2030: हरित विकास का रोडमैप : आने वाले वर्षों में पर्यावरणीय शासन पूरी तरह डेटा-आधारित, पारदर्शी और तकनीक-संचालित होगा। "भविष्य की दृष्टि 2030" के अंतर्गत राज्य में स्मार्ट मॉनिटरिंग, डिजिटल पर्यावरणीय प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण की उन्नत प्रणालियाँ तथा जनसहभागिता आधारित संरक्षण मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। यह दृष्टिकोण केवल प्रदूषण नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण और उच्च जीवन गुणवत्ता उपलब्ध कराने का व्यापक प्रयास है।

तकनीक और प्रकृति के समन्वय से बनेगा सुरक्षित भविष्य : विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह संदेश देता है कि पृथ्वी की सुरक्षा केवल सरकारों का दायित्व नहीं, बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है ।छत्तीसगढ़ में ड्रोन आधारित निगरानी, CAAQMS, CEMS, GPS ट्रैकिंग, आधुनिक प्रयोगशालाएँ और जनभागीदारी आधारित कार्यक्रम पर्यावरणीय शासन को नई दिशा दे रहे हैं। ये पहलें न केवल प्रदूषण नियंत्रण को अधिक प्रभावी बना रही हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, सुरक्षित जल और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने की मजबूत नींव भी तैयार कर रही हैं।

प्रकृति और प्रगति के बीच संतुलन स्थापित करने का यह प्रयास ही छत्तीसगढ़ को हरित विकास की नई पहचान दे रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर यही संकल्प सबसे महत्वपूर्ण है - एक ऐसा प्रदेश, जहाँ विकास की गति भी बनी रहे और पर्यावरण की शुद्धता भी।

संजय उवाच

प्रो. संजय द्विवेदी

त्यौहार का मौका है, एक दोस्त दूसरे को बुलाता है और चाकू से गोंदकर मार डालता है। दोनों अलग-अलग समुदायों से हैं। दोस्ती के नाम पर कत्ल जाहिर है धोखा है, जघन्य अपराध है। उसे सजा मिल चुकी है। पुलिस ने उसे अगले दिन उस युवा को एनकाउंटर में मार गिराया। कहानी खत्म हो जानी चाहिए पर सच तो यह है कि कहानी अब शुरू हो रही है। आखिर हम अपने नौजवानों को क्या सिखा रहे हैं? वे इतने हिंसक क्यों हो रहे हैं? कौन सी शिक्षा, कैसे परिवार और कैसी परवरिश हो रही है, जहां कत्ल आम बात है। इतना ही नहीं, नौजवान इंस्टा पर रील भी पोस्ट करता है कि मैंने कत्ल कर दिया है। क्या कत्ल इतनी आम बात है। इसके पहले जयपुर में भी दो लोग ऐसा ही काम करते हैं, एक दर्जी को उसकी दुकान पर कत्ल करते हैं, वीडियो बनाते हैं। बाद में मारे जाते हैं। इतने बड़े देश में ऐसे कुछ उदाहरण यह कहकर टाले जा सकते हैं, इसमें क्या बात है। ये अपराध हैं। मनोविकार हैं। रोके नहीं जा सकते। लेकिन मामला सिर्फ अपराध का नहीं उस प्रेरणा का है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। हिंदुस्तान का एक भी नौजवान हिंसा या प्रतिहिंसा में मारा जा रहा है, तो यह दुख का कारण है। क्या हम अपनी औलादों को इसीलिए दुनिया में लाए हैं कि वे किसी को मार दें और फिर खुद मार डाले जाएं।

इस हिंसक समय में !

हिंसा और आतंकवाद के विरुद्ध चयनित दृष्टिकोण से बचे समाज

इन दिनों देश भर के तमाम हिस्सों से सांप्रदायिक उफान, गुस्सा और हिंसक घटनाएं सुनने में आ रही हैं। दूसरी ओर तमाम अतिवादी संगठन इंटरनेट के माध्यम से हमारे देश की युवा शक्ति को फांसने और अपने साथ लेने की कवायद में जुटे हैं। हम देखें तो सांप्रदायिकता और राजनीति के रिश्ते आपस में इस तरह जुड़े हैं, जिसमें यह कहना कठिन है कि कौन किससे ताकत पा रहा है? सच तो यह है कि राजनीति उन्हें इस्तेमाल करने के कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहती। सवाल सिर्फ हिंदू-मुसलमान का है या राजनीति का भी है। दंगे जब होते हैं या कराए जाते हैं तब इसका भी विश्लेषण होना चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या हैं। पता चलेगा कि पंथ के बजाए कोई और मामला है, तथा हिंदू-मुसलमान का इस्तेमाल कर लिया जाता है। यह मानना बहुत कठिन है कि कोई भी समाज, जाति, परिवार या वर्ग अपने परिवार के साथ सुख-शांति से नहीं रहना चाहता।

हिंसा किसे प्यारी है? आतंकवाद को कौन पालना चाहता है? लेकिन हिंसा होती है, और आतंकवाद बढ़ता है। यानि यह सामान्य मनुष्यों का काम नहीं है। कोई भी स्वस्थ मनुष्य न तो हिंसा करेगा, न ही वह किसी आतंकी कारर्वाई का समर्थन करेगा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वे साधारण लोग नहीं हैं। वे दिमागी तौर पर अस्वस्थ, मनोविकारी, कुंठित और अपराधी मानसिकता के लोग हैं। लेकिन आश्चर्य यह कि शेष समाज का समर्थन पाने में वे सफल हो जाते हैं। कोई समय से, कोई पैसे से, कोई हथियारों से उन्हें समर्थन देता है। आखिर ये समर्थन देने वाले लोग कौन हैं? आप वैश्विक स्तर से स्थानीय हिंसक समूहों को देखें तो उन्हें मदद करने वाले हाथ साधारण नहीं है। आईएस के मनुष्यता-विरोधी अभियान को तमाम देशों से मदद के प्रमाण मिले ही हैं। भारत में माओवादी आतंक को भी तमाम ताकतों का समर्थन मिलता रहा है। इसी तरह सांप्रदायिकता के विषधरों को भी समाज के तमाम तबकों से अलग-अलग रूपों में समर्थन मिलता है। वरना क्या कारण है कि हिंसक घटनाओं के पीछे हमारी राजनीतिक पार्टियों के तार जुड़े नजर आते हैं? जो नेता अपने समाज की गरीबी, अशिक्षा, बदहाली और पिछड़ेपन पर खामोश रहते हैं, वे अराजक तत्वों को समर्थन देते नजर आते हैं। लगता है उन्हंद भारत के लोकतांत्रिक- जनतांत्रिक चरित्र पर विश्वास नहीं है।

भारत का संविधान और कानून सबके लिए बराबर है। संविधान के दायरे में आकर अपने अधिकारों की मांग करना भी ठीक है। समूची दुनिया में मुस्लिम समाज के सामने ये सवाल खड़े हैं। अपनी प्रतिक्रिया में संयम न रखना आज मुस्लिम समाज के सामने एक चुनौती ही है। अपने पंथ की ऐसी आक्रामक छवि बनता देखकर भी उसके नेताओं में चिंता नहीं दिखती। राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल करते आए हैं, करते रहेंगें। किंतु यह भी सोचना होगा कि आप कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे? नकली नोटों के कारोबारी, हथियारों के सप्लायर, अवैध कारोबारों में लिप्त लोग अगर समाज का इस्तेमाल कर अपनी ताकत को बचाना चाहते हैं तो समाज को भी होशियार होना चाहिए। राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, समाज के अगुआ लोगों को इस तरह की प्रवृत्ति के खिलाफ समाज को जागृत करना होगा। लोगों की भावनाओं से खेलने का काम बहुत हो चुका। अब लोगों में वैज्ञानिक सोच जगाने और मानवता को सबसे बड़ा दर्जा देने का विचार आगे बढ़ाना होगा। गलत करने वाले को सजा देने वाले हम कौन हैं? कानून को हाथ में लेकर, तोड़फोड़ और आगजनी कर क्या हम अपने पंथ, उसकी पवित्र शिक्षाओं का आदर कर रहे हैं?

हमारे युवा गुमराह होकर आतंकवाद की राह पकड़कर युवा अवस्था में ही मौत की भेंट चढ़ रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि हमारे समाज के अगुआ, धमर्गुरू, शिक्षक, बुद्धिजीवी सब हार रहे हैं। भारत हार रहा है। एक लोकतंत्र में होते हुए भी अगर हमारी सांसें घुट रही हैं, हम विचारों को व्यक्त करने के बजाए दहशत पैदा कर अपनी कुठाएं निकाल रहे हैं, तो हमें सोचना होगा कि आखिर हमने कैसा भारत बनाया है। भारत जैसे देश में जहां सब पंथों, समाजों और वर्गो को सम्मान और आदर के साथ रहने के समान अवसर हैं, वहां हिंसा की राह पकड़ रहा कोई भी समूह या व्यक्ति भारत-प्रेमी नहीं कहा जा सकता। अपने रोष और गुस्से को निकालने के लिए तमाम संवैधानिक और सत्याग्रही तरीके हमारी परंपरा में हैं, हम उनका अनुसरण करें और न्याय प्राप्त करें। एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए जनता का जाग्रत होना भी जरूरी है।

समाज को बांटकर शक्ति नहीं पायी जा सकती। सब साथ मिलकर विकास करें। सपनों में रंग भरें तभी भारत बचेगा और तभी हमारी शान दुनिया में बनेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि राजनीति में अगर पंथिक राजनीति हस्तक्षेप करेगी, सांप्रदायिक भावनाएं वोट-बैंक के निर्माण में मददगार होंगी। हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ हमारा दृष्टिकोण चयनित होगा, एक हिंसा पर खामोशी, दूसरी हिंसा पर बवेला होगा, तब सांप्रदायिकता से कैसे लड़ेगें? काश राजनीति वाणी संयम और भारत-प्रेम की भावनाओं से लबरेज होती तो हम ऐसे सामाजिक संकटों का आसानी से मुकाबला कर पाते। लेकिन अफसोस राजनीतिक दलों के पास तिरंगे से ज्यादा बड़े और ज्यादा गहरे रंगों वाले झंडे हैं। राष्ट्रप्रथम की भावना ही हमें इस तरह के हिंसक अभियानों से बचा सकती है। वरना यह खून यूं ही बहता रहेगा और हाथ आएगा सिर्फ दुख। बहुत बड़ा दुख! अपने नौजवानों को खोते जाने का दुख!

(लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं। पूर्व में भारतीय जनसंचार संस्थान-आईआईएमसी के महानिदेशक रह चुके हैं।)

खास खबर

राष्ट्रीय स्तर पर चमका जशपुर का सरडीह, स्वच्छ व हरित ग्राम श्रेणी में देश में तीसरा स्थान

नई दृष्टिबिंदु / जशपुर

जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड की ग्राम पंचायत सरडीह ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के अंतर्गत सरडीह पंचायत को थीम-5 स्वच्छ एवं हरियाली ग्राम श्रेणी में संयुक्त रूप से देशभर में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के लिए पंचायत को 25 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है।

नई दिल्ली स्थित स्कोप कन्वेंशन सेंटर में 3 जून को आयोजित राष्ट्रीय समारोह में ग्राम पंचायत सरडीह के सरपंच रामजी राम भगत एवं सचिव ईश्वर प्रसाद यादव ने यह सम्मान ग्रहण किया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री एवं मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार, उप संचालक पंचायत सुश्री कुसुम बड़ा, जनपद पंचायत बगीचा की अध्यक्ष श्रीमती गायत्री नागेश तथा एडीपीएम नवनीत कुमार साहू भी उपस्थित रहे।

कलेक्टर रोहित व्यास ने इस उपलब्धि पर ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों को बधाई देते हुए कहा कि सरडीह की सफलता सामुदायिक सहभागिता, नवाचार और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह उपलब्धि जिले की अन्य पंचायतों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी। जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार ने कहा कि सरडीह ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है। सरडीह में 109 घरों में सौर ऊर्जा आधारित पंप लगाए गए हैं, जिससे सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो रहा है। किसान टमाटर, मिर्च, खीरा सहित विभिन्न उद्यानिकी फसलों की खेती कर आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ उठा रहे हैं। इससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन की दिशा में पंचायत द्वारा स्थापित 12 सोलर स्ट्रीट लाइटें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक में भी मिली सरडीह को जगह : समारोह के दौरान पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विशेष पुस्तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 का विमोचन भी किया गया। इस पुस्तक में सरडीह पंचायत के स्वच्छता, जल संरक्षण, हरित विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और सामुदायिक सहभागिता से जुड़े नवाचारों को विशेष रूप से शामिल किया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों को पुस्तक की प्रति भी प्रदान की गई।

'सनराइज टू सनसेट' पर्यटन सर्किट : टाटामारी में सुनहरी सुबह, पुसपाल में हुआ मनमोहक शाम

बस्तर का नया पर्यटन सर्किट देशभर के पर्यटकों को करेगा आकर्षित

नई दृष्टिबिंदु / बस्तर

बस्तर की पहचान अब केवल प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह क्षेत्र तेजी से पर्यटन विकास के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। कभी नक्सली गतिविधियों के कारण चर्चा में रहने वाला क्षेत्र अब पर्यटन और विकास की नई कहानी लिखने की तैयारी में है। इसी दिशा में कोण्डागांव वनमंडल द्वारा ग्राम पुसपाल को केंद्र में रखकर एक नए पर्यटन सर्किट का विकास किया जा रहा है, जो बस्तर के पर्यटन मानचित्र में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने वाला है।

इस नई पहल का सबसे बड़ा आकर्षण यह होगा कि पर्यटक एक ही दिन में टाटामारी की पहाड़ियों से उगते सूरज का अद्भुत दृश्य और पुसपाल में ढलते सूरज की मनोहारी छटा का आनंद ले सकेंगे। प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक आस्था और साहसिक गतिविधियों का अनूठा संगम इस सर्किट को विशेष पहचान दिलाएगा।

केशकाल से चित्रकोट की यात्रा होगी आसान और रोमांचक

प्रस्तावित पर्यटन सर्किट के विकसित होने से केशकाल से चित्रकोट जलप्रपात तक की यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक और कम समय में पूरी की जा सकेगी। पर्यटक अपनी यात्रा की शुरुआत केशकाल स्थित टाटामारी से कर सकेंगे, जहां सूर्योदय का विहंगम दृश्य उन्हें प्रकृति के अद्भुत अनुभव से रूबरू कराएगा।

इसके बाद पर्यटक चौत्यगृह, भोंगापाल और गोबरहीन जैसे धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। गोबरहीन स्थित प्राचीन शिवलिंग क्षेत्र की आध्यात्मिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। दिनभर की यात्रा के बाद पर्यटक पुसपाल पहुंचकर सूर्यास्त के मनोरम दृश्य का आनंद ले सकेंगे, जो इस पूरे पर्यटन अनुभव को यादगार बना देगा।

कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र अब विकास और विश्वास की नई किरण

यह क्षेत्र कभी नक्सली गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता था, जिसके कारण यहां की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों की पहुंच से दूर रही। राज्य सरकार की प्रभावी रणनीति, सुरक्षा बलों के प्रयासों और विकासोन्मुखी योजनाओं के चलते अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास का वातावरण बनने से पर्यटन की नई संभावनाएं सामने आ रही हैं। नया पर्यटन सर्किट इसी बदलाव का प्रतीक माना जा रहा है, जो क्षेत्र की सकारात्मक छवि को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में सहायक होगा।

स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य पर्यटन विकास के साथ स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी है। पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय युवाओं को गाइड, होमस्टे संचालन, परिवहन, खानपान, हस्तशिल्प और अन्य सेवाओं के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था के विकसित होने से क्षेत्र में आय के नए स्रोत पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

राफ्टिंग, कॉटेज और एडवेंचर स्पोर्ट्स बनेंगे आकर्षण का केंद्र

इस पर्यटन सर्किट में पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा। यहां कॉटेज निर्माण, राफ्टिंग जैसी साहसिक गतिविधियों तथा विभिन्न एडवेंचर स्पोर्ट्स की तैयारियां की जा रही हैं। इससे प्रकृति प्रेमियों के साथ-साथ रोमांच पसंद करने वाले पर्यटकों को भी नया गंतव्य मिलेगा।

दो जिलों की सीमा पर विकसित होगा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट

इस पर्यटन परियोजना का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा कोण्डागांव जिले के नारायणपुर सीमा से लगे क्षेत्रों में विकसित किया जाएगा, जबकि शेष 30 प्रतिशत कार्य बस्तर जिले के अंतर्गत आने वाले कोण्डागांव वनमंडल क्षेत्र में किया जाएगा। परियोजना के लिए प्रारंभिक खाका और बजट तैयार किए जा चुके हैं तथा जमीनी स्तर पर आवश्यक प्रक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं।

परियोजना के पूर्ण होने के बाद टाटामारी से पुसपाल तक का यह पर्यटन सर्किट बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और विकास की नई तस्वीर प्रस्तुत करेगा। यह न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन में आर्थिक समृद्धि और नए अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

स्वच्छता ही सेवा : जनजागरूकता और जनभागीदारी से स्वच्छता अभियान को मिल रही है नई दिशा

नई दृष्टिबिंदु / मनेन्द्रगढ़

जिले में स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने के उद्देश्य से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में विकासखंड मनेन्द्रगढ़ की ग्राम पंचायत सिरियाखोह के स्वच्छता ग्राहियों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए पुनर्चक्रण योग्य कचरे का संग्रहण एवं विक्रय किया तथा ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का सराहनीय कार्य किया।

स्वच्छता ग्राहियों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई चनवारीडांड को 20 किलोग्राम रंगीन पन्नी, 14 किलोग्राम सफेद पन्नी एवं 14 किलोग्राम प्लास्टिक बोतल सहित कुल 48 किलोग्राम सूखा कचरा विक्रय किया गया। इसके साथ ही घर-घर जाकर ग्रामीणों को सड़क, नालियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर कचरा नहीं फेंकने, घरों एवं आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने तथा कचरे का उचित प्रबंधन करने के लिए प्रेरित किया गया।

इस अभियान की सफलता में क्लस्टर समन्वयक श्रीमती प्रभा प्यासी का विशेष योगदान रहा। उनके अथक प्रयासों, सतत मार्गदर्शन एवं स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने की प्रतिबद्धता से ग्रामीणों में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने स्वच्छता ग्राहियों के साथ मिलकर लोगों को स्वच्छ वातावरण के महत्व से अवगत कराया तथा कचरा पृथक्करण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की उपयोगिता समझाई।

अभियान के दौरान सरपंचों एवं सचिवों ने भी ग्रामीणों से गांव को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने, घरों से निकलने वाले कचरे को स्वच्छता ग्राहियों को सौंपने तथा सार्वजनिक स्थलों पर कचरा न फैलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज और बेहतर भविष्य की आधारशिला है। जिला प्रशासन ने जिले वासियों से आग्रह किया है कि वे अपने घर, मोहल्ले और गांव को स्वच्छ रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं। सड़क, नाली, तालाब एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने से बचें तथा स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।

जनसहभागिता और जागरूकता से ही स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर जिले का सपना साकार किया जा सकता है। स्वच्छता अपनाएं, कचरा न फैलाएं और स्वच्छ एमसीबी के निर्माण में अपना योगदान दें इसी संदेश के साथ जिले में स्वच्छता जागरूकता अभियान निरंतर जारी है।

सुशासन तिहार केवल आयोजन, धरातल पर बेबस किसान - ताम्रध्वज साहू

पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने पदाधिकारियों के साथ दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सहकारी समितियों का किया दौरा

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

प्रदेश में खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले किसानों को हो रही खाद की किल्लत (यूरिया, डीएपी) और टोकन व्यवस्था में आ रही समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू एवं क्षेत्र के सभी प्रमुख पदाधिकारीयों के साथ दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नगपुरा, ग्राम थनौद, अंडा ग्राम कुथरेल, बोरीगारका ग्राम मंचादुर एवं नगर पंचायत उतई में सेवा सहकारी समितियों का दौरा किया।

श्री साहू सहकारी समितिओं और खाद वितरण केंद्रों पर पहुंचकर समिति प्रबंधकों एवं किसानों से सीधा चर्चा किया। सोसायटी में किसानों से चर्चा के दौरान पता चला की खाद-बीज का पर्याप्त भंडारण नहीं है, जिसके कारण सभी अन्नदाता तपती धूप में लंबी-लंबी लाइनों में लगने को मजबूर हैं। परेशान और बेबस किसान साथियों में इस अव्यवस्था को लेकर भारी आक्रोश है। सुशासन का दावा करने वाली भाजपा सरकार विज्ञापनों से बाहर निकले और किसानों की सुध ले। पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने का आरोप है कि राज्य के किसान बुवाई के महत्वपूर्ण समय में यूरिया और डीएपी की किल्लत से जूझ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि भाजपा सरकार सुशासन तिहार जैसे आयोजनों में व्यस्त है और जमीनी स्तर पर अन्नदाताओं की अनदेखी कर रही है।मैं उच्च अधिकारियों व जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस गंभीर समस्या पर तुरंत संज्ञान लें। इस गुत्थी को समझें कि आखिर खाद जा कहां रही है और किसान तक क्यों नहीं पहुंच रही।

कांग्रेस के वक्ताओ का कहना हैं कि एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार लगातार दावा कर रही है खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध है और किसानों को किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर छोटे किसानों को डीएपी नहीं मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं अधिकांश समितियों में आवश्यक खाद के साथ ही डी ए पी जैसे अति जरूरी खाद उबलब्ध नहीं है और कही कही कुछ कुछ खाद है भी तो सरकारी आदेश प्रति एकड़ 25 किलो डी ए पी, एक बोरा यूरिया, राखड़, पोटास ही नाममात्र का दिया एजा रहा है इसी तरह बीज का भी समुचित भंडारण समितियों में नहीं होने से किसान बीज के लिए भटका रहे है कई समिति के सरना धान बीज करगायुक्त और अमानक वितरण की भी शिकायत किसानों ने किया है। इससे सरकारी दावों और वास्तविक व्यवस्था के बीच अंतर दिखाई दे रहा है।

इस दौरा कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख, पूर्व अध्यक्ष केश कला नंद कुमार सेन, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस रिवेन्द्र यादव, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस टिकेश्वरी लाल देशमुख, महामंत्री जिला कांग्रेस योगिता चन्द्रकार, महामंत्री लक्ष्मी साहू, जनपद सदस्य झमित गायकवाड़, रविंद्र सिन्हा, कैलाश सिन्हा, ताम्रज सिन्हा, मंडल अध्यक्ष नंद कुमार साहू, देवराज चतुर्वेदी, दिवाकर गायकवाड़, धर्मेंद्र बंजारे, मुरारी देशमुख, हरेंद्र देव, तारकेश्वर चन्द्रकार, सरपंच अंडा दिग्विजय सिन्हा, रुपेश देशमुख, डॉ पिलेश्वर साहू जनपद उपाध्यक्ष राकेश हिरवानी, गीता महानन्द, जामवंत गजपाल, बेकुंठ, राजेश साहू, वेदनारायण, दुलरवा सोनबेर, शिवनारायण दिल्लीवार, युगल साहू चाँदखान, कृष्णा साहू, निरंजन राजपूत, अरुण वर्मा, डिकेंद्र हिरवानी, द्वारीका साहू, डॉ प्रहलाद वर्मा, बहादुर नेताम, मीना सूयर्वशी, योगेश, जनार्दन साहू, गजेंद्र काकड़े, घनश्याम गजपाल, सहित जिला कांग्रेस एवं ब्लॉक कांग्रेस के साथ साथ मंडल, सेक्टर, पंचायत वार्ड तथा बूथ कार्यकर्त्ताओं सहित एवं क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मेडिटेशन को जीवनशैली का हिस्सा बनाएं - राज्यपाल

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा है कि मेडिटेशन (ध्यान) को जीवनशैली का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। आज के तनावपूर्ण और व्यस्त जीवन में ध्यान मानसिक शांति, एकाग्रता और कार्यकुशलता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। लोक भवन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आयोजित तीन दिवसीय ध्यान शिविर के दूसरे दिन राज्यपाल रमेन डेका भी उपस्थित रहे। इस दौरान हार्टफुलनेस संस्था, अमलेश्वर से आए प्रशिक्षकों ने अधिकारियों और कमर्चारियों को ध्यान की विभिन्न विधियों की जानकारी दी तथा उनका व्यावहारिक अभ्यास भी कराया।

राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कार्यभार के कारण तनाव एक सामान्य समस्या बन गया है। ऐसे में ध्यान व्यक्ति को मानसिक संतुलन बनाए रखने, तनाव कम करने और सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करने में सहायता करता है। राज्यपाल ने अधिकारियों और कमर्चारियों से प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नियमित ध्यान का अभ्यास व्यक्ति के जीवन में आत्मिक संतोष, सकारात्मकता और अद्भुत आनंद का अनुभव कराता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बेहतर संतुलन स्थापित कर सकता है।

शिविर में हार्टफुलनेस संस्था, अमलेश्वर के प्रशिक्षकों ने ध्यान के महत्व, उसकी प्रक्रिया और दैनिक जीवन में उसके लाभों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों को ध्यान के व्यावहारिक सत्र में शामिल कराकर उसका अनुभव भी कराया। इस अवसर पर प्रशिक्षकों ने राज्यपाल श्री डेका को मेडिटेशन और आत्मिक विकास से संबंधित पुस्तकें भी भेंट कीं।

सिनेमा में वापसी करना चाहती हैं स्नेहा उल्लाल

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल ने हाल ही में अपने करियर और निजी जिंदगी को लेकर कई दिलचस्प बातें शेयर कीं। साथ ही ऐश्वर्या राय से उनकी तुलना होने पर भी खुलकर चर्चा की।

इंटरव्यू में स्नेहा ने बताया कि जब उन्हें फिल्म का ऑफर मिला, तब वो सिर्फ 17 साल की थीं और हाल ही में कॉलेज में एडमिशन लिया था। उसी दौरान उनकी मां कैंसर का इलाज करवा रही थीं। घर का माहौल काफी उदास था। ऐसे में उन्होंने ये फिल्म सिर्फ इसलिए साइन की ताकि परिवार का ध्यान थोड़ी देर के लिए उस मुश्किल समय से हट सके। उन्होंने कहा, 'मां को घूमना-फिरना बहुत पसंद था, इसलिए मैंने इस ऑफर को हां कह दिया। उस फैसले ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी, चाहे मुझे एक्टिंग में दिलचस्पी थी या नहीं।' स्नेहा ने यह भी माना कि रातोंरात मिली शोहरत की अपनी कीमत होती है। उन्होंने कहा कि स्टार बनने के बाद उनकी आजादी, कॉलेज लाइफ और टीनएज सब कहीं पीछे छूट गया। उन्होंने कहा, 'मैं 16 साल की उम्र से सीधे बड़ी हो गई। उस समय समझ नहीं आया, लेकिन अब एहसास होता है कि मैंने बहुत कुछ मिस किया।'

बातचीत में स्नेहा ने ऐश्वर्या राय बच्चन से होने वाली तुलना पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जब ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड बनी थीं, तभी से लोग कहते थे कि दोनों की शक्ल काफी मिलती है। बाद में सलमान खान के साथ डेब्यू करने की वजह से लोगों ने अलग-अलग बातें बनानी शुरू कर दीं, लेकिन मैं उस समय बहुत छोटी थी, इसलिए इन चीजों का मुझ पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। वर्कफ्रंट की बात करें तो बॉलीवुड के बाद स्नेहा ने साउथ फिल्मों में भी काम किया। अब वो धीरे-धीरे हिंदी सिनेमा में वापसी कर रही हैं। स्नेहा का कहना है कि वो इंडस्ट्री में अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहती हैं और अब उन्हें साफ पता है कि वो किस तरह की एक्ट्रेस बनना चाहती हैं।

मगर मलयालम फिल्मों में काम नहीं करना चाहतीं जाह्नवी

अभिनेत्री जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' सिनेमाघरों में रिलीज को तैयार है। हिंदी के साथ ही साउथ की फिल्मों में काम कर चुकीं जाह्नवी कपूर ने कहा कि वह दोबारा मलयालम सिनेमा में काम नहीं करना चाहती हैं। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई। हाल ही में फिल्म 'परम सुंदरी' में काम करने के बाद उन्होंने माना कि मलयालम भाषा उनके लिए काफी मुश्किल साबित हुई। जाह्नवी कपूर ने आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि साल 2024 में तेलुगु फिल्म 'देवरा: पार्ट 1' से दक्षिण भारतीय सिनेमा में डेब्यू करने के बाद अब वे खुद को कई भाषा जानने वाली अभिनेत्री मानती हैं। उन्होंने बताया, 'सच कहूं तो मुझे सभी भाषाएं सीखनी हैं। लेकिन मलयालम भाषा की फोनेटिक्स (उच्चारण) मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रही। मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा मलयालम में काम करना चाहिए क्योंकि यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यह बहुत खूबसूरत और प्यारी भाषा है, लेकिन तमिल और तेलुगु की आवाजों से मैं काफी हद तक परिचित हूं।'

साल 2018 में फिल्म 'धड़क' से करियर की शुरुआत करने वाली जाह्नवी कपूर 'गुंजन सक्सेना', 'मिली' और 'देवरा: पार्ट 1' जैसी फिल्में दे चुकी हैं। जाह्नवी तेलुगु फिल्मों का भरपूर आनंद ले रही हैं और तमिल सिनेमा में भी काम करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा, 'मैं तेलुगु फिल्मों में काम करने का सच में आनंद ले रही हूं। मैं तमिल फिल्मों में भी काम करना चाहूंगी।' 'पेड्डी' एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। ट्रेलर में गांव की जिंदगी, मेहनत, संघर्ष और खेलों के प्रति जुनून साफ दिखाई दे रहा है। राम चरण एथलीट 'पेड्डी' की भूमिका में हैं, जो क्रिकेट, कुश्ती और दौड़ जैसे कई खेलों के लिए मैदान में उतरता है। वर्तमान में जाह्नवी तेलुगु फिल्म 'पेड्डी' की रिलीज की तैयारी में व्यस्त हैं। बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जाह्नवी के साथ राम चरण लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म में मजबूत सपोर्टिंग कास्ट भी है, जिसमें शिव राजकुमार, दिव्येंदु और बोमन ईरानी शामिल हैं। फिल्म गांव के माहौल, एक्शन और भावनात्मक कहानी का रोमांचक मिश्रण है।

बाबिल खान ने शुरू की इस मलयालम फिल्म की शूटिंग

अभिनेता इरफान खान के बेटे बाबिल खान मलयालम सिनेमा में कदम रखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी पहली मलयालम फिल्म 'गांधी बाजार संडे मार्केट' की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म का निर्देशन जाने-माने फिल्ममेकर बाबू जनार्दन कर रहे हैं। यह बाबिल खान के अभिनय करियर में एक नए दौर की शुरुआत है।

मलयालम सिनेमा से प्रभावित हैं बाबिल

अपकमिंग फिल्म 'गांधी बाजार संडे मार्केट' में अपर्णा बालमुरली, दीपक परंबोल, निखिल नायर, जॉनी एंटनी, जगदीश, सुधीर करमना, आथमिया राजन और जयशंकर जैसे कलाकार होंगे। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बारे में बात करते हुए, बाबिल ने बताया कि वह हमेशा से मलयालम सिनेमा और उसकी कहानी कहने के अंदाज से प्रभावित हैं।

मलयालम सिनेमा की तारीफ की

उन्होंने कहा 'मलयालम सिनेमा ने हमेशा मेरे दिल में एक बहुत ही खास जगह बनाई है। यहां कहानियां जिस ईमानदारी, संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई के साथ कही जाती हैं, वह बेमिसाल है। सिलीगुड़ी में 'गांधी बाजार संडे मार्केट' की शूटिंग शुरू करना मेरे लिए बेहद रोमांचक और रचनात्मक है।'

ईशा सिंह ने याद किए संघर्ष के दिन

मनोरंजन जगत की चकाचौंध भरी दुनिया में नाम बनाना आसान नहीं है। किस्मत और मेहनत के दम पर काम तो मिल जाता है, लेकिन इंडस्ट्री की थका देने वाली भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी के कारण कई लोग यहां से दूरी बना लेते हैं। ऐसा ही कुछ अनुभव अभिनेत्री ईशा सिंह के साथ हुआ था। अभिनेत्री ईशा सिंह ने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया कि उनका शुरुआती सफर बेहद मुश्किलों और चुनौतियों से भरा रहा था। अभिनेत्री ने शुरुआती दिनों के संघर्ष को याद करते हुए बताया, 'मेरा शुरुआती दौर यकीनन बहुत मुश्किलों भरा था। एक वक्त तो ऐसा भी था, जब परेशान होकर मैंने अपना पहला शो बीच में ही छोड़ दिया था और वापस अपने घर भोपाल चली गई थी, लेकिन मेरा मानना है कि भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। उनकी कृपा और मेरी मेहनत की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर खड़ी हूं।' हालांकि, ईशा ने ये भी स्पष्ट किया कि इंडस्ट्री में उन्हें लोगों का भी बहुत साथ मिला और कभी आउटसाइडर जैसा महसूस नहीं हुआ। उन्होंने बताया, 'मुझे यहां पर बहुत अच्छे लोग मिले, जिन्होंने कभी यह एहसास होने नहीं दिया कि मैं बाहर से आई हूं। हां, शुरुआत में कुछ मुश्किलें आईं क्योंकि मैं बिल्कुल नई थी और काम सीख रही थी, लेकिन तब से लेकर अब तक मैंने एक लंबा सफर तय किया है। दर्शकों ने मुझे जो प्यार दिया उसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूं। अभिनेत्री ईशा सिंह कई म्यूजिक वीडियोज और रियलिटी शो बिग-बॉस में भी नजर आ चुकी हैं, जहां उन्हें दर्शकों से प्यार मिला, तो कई बार ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। ट्रोलिंग को लेकर अभिनेत्री का कहना है, 'रियलिटी शोज आपको जनता के सामने एक खुली किताब की तरह रख देते हैं। लोग लगातार आपकी आलोचना करते हैं, लेकिन अब मैंने सीख लिया है कि इन नकारात्मक बातों का खुद पर असर न होने दूं। आज मैं मानसिक और भावनात्मक, दोनों ही स्तर पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी हूं। जब आईएएनएस ने अभिनेत्री ईशा सिंह से पूछा, 'खबरें हैं कि आप अपने आने वाले किसी प्रोजेक्ट में एक 'ऑटिस्टिक' किरदार निभाती हुई नजर आ सकती हैं। आपको इस तरह के संवेदनशील विषयों की ओर क्या चीज आकर्षित करती है? अभिनेत्री ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, 'यह एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है और सही समय आने पर मैं इसके बारे में जरूर बात करूंगी, लेकिन अभी के लिए, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्म 'ऑब्सेस' पर ही केंद्रित है। यह एक इमोशनल और बेहद प्रभावशाली फिल्म है और मैं चाहती हूं कि दर्शक इसे सिनेमाघरों में जाकर जरूर देखें।'

लस्ट स्टोरीज 3 में नजर आएंगी राधिका मदान; स्ट्रगल्स पर की खुलकर बात

राधिका मदान इन दिनों अपनी हालिया रिलीज 'सूबेदार' में शानदार परफॉर्मेंस के लिए खूब तारीफें बटोर रही हैं। अब वह शकुन बत्रा की 'लस्ट स्टोरीज 3' के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिसमें वह अली फजल के साथ नजर आएंगी।

बातचीत में राधिका ने कहा, 'मैं शकुन बत्रा के काम की बहुत बड़ी फैन रही हूं। जब मुझे इस फिल्म के बारे में पता चला, तो मैंने 'लस्ट स्टोरीज 3' के लिए ऑडिशन देने की रिक्वेस्ट की। भगवान की कृपा से मुझे यह मौका मिल गया।' उन्होंने आगे कहा, 'मैं एक औसत परफॉर्मेंस देने का रिस्क नहीं ले सकती। हर रोल के लिए बहुत लोग लाइन में खड़े होते हैं। अगर मैं अच्छा नहीं करूंगी, तो कोई मुझे दूसरा मौका नहीं देगा। मेरे लिए हर काम 'करो या मरो' जैसा होता है। अगर मुझे इस इंडस्ट्री में टिकना है, तो मुझे हर बार बेस्ट देना होगा।'

मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है

राधिका ने अपने स्ट्रगल के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, 'मैं लाइन में खड़ी रही हूं, बहुत मेहनत की है। आज भी अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जहां लोग मुझे कास्ट करने के बारे में नहीं सोचते, तो मैं खुद ऑडिशन मांगती हूं और मुझे इसमें कोई झिझक नहीं होती। मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है।'

सपनों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब मुझे ऑडिशन का मौका ही नहीं मिलता और सिर्फ मेरे सरनेम की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर मैं ऑडिशन देकर रिजेक्ट होती हूं, तो मुझे सुकून मिलता है क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने अपना 100% दिया। अगर मुझे फिर से लाइन में लगना पड़े, तो भी मुझे कोई शर्म नहीं है।

'12वीं फेल' के हिट होने के बाद मैंने बहुत प्रेशर ले लिया था

'12वीं फेल' से सीधे दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली मेधा शंकर की कहानी जितनी चमकदार दिखती है, उतनी ही जमीन से जुड़ी भी है। नेशनल क्रश का टैग मिला लेकिन उन्होंने इसे बोझ नहीं बनाया क्योंकि उनका फंडा साफ है, जिंदगी में ज्यादा लोड नहीं लेना। कभी इसी राह पर कदम रखने के फैसले पर घर में सवाल उठे लेकिन उन्होंने भरोसा नहीं छोड़ा। स्ट्रगल, रिजेक्शन और मेहनत के बीच मेधा ने खुद को अपने तरीके से बिना ज्यादा शोर के साबित किया। हाल ही में अपनी फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी' के सिलसिले में लखनऊ आईं मेधा शंकर ने हमारे साथ दिलचस्प बातें शेयर कीं, जहां पर्दे के पीछे की उनकी असली कहानी, संघर्ष और सोच बिना किसी लाग-लपेट के सामने आईं।

मैं जिंदगी में ज्यादा लोड नहीं लेती

नेशनल क्रश बनने में मेरा कोई योगदान नहीं था। जनता को प्यार हो गया तो हो गया। इस वजह से मैंने इस टैग का कोई प्रेशर नहीं लिया। नेशनल क्रश बनना तो एक अलग बात है लेकिन 12वीं फेल जैसी फिल्म का इतना अच्छा चलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। शुरुआत में घबराहट हुई क्योंकि मैं वैसे भी आउटसाइडर हूं तो डर था कि आगे मुझे काम मिलेगा या नहीं। क्या करूं, क्या नहीं, इस पर बहुत लोग राय दिया करते थे। फिर मुझे लगा कि इतना सोचने से कुछ नहीं होगा। चाहे कितना भी दिमाग लगा लूं, होगा वही जो होना है इसलिए बहुत सी चीजें भगवान के भरोसे छोड़ देती हूं। अगर दस स्क्रिप्ट आईं और उनमें से दो पसंद आईं तो मैं उन्हें हां कह देती हूं। मैं जिंदगी में ज्यादा लोड नहीं लेती।

12वीं फैल जैसी फिल्म का इतना अच्छा चलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। शुरुआत में घबराहट हुई क्योंकि मैं वैसे भी आउटसाइडर हूं तो डर था कि आगे मुझे काम मिलेगा या नहीं। क्या करूं, क्या नहीं, इस पर बहुत लोग राय दिया करते थे। फिर मुझे लगा कि इतना सोचने से कुछ नहीं होगा। चाहे कितना भी दिमाग लगा लूं, होगा वही जो होना है इसलिए बहुत सी चीजें भगवान के भरोसे छोड़ देती हूं।

बिना सफल हुए कोई भरोसा नहीं करेगा

'12वीं फेल' से पहले का दौर मुश्किल भरा था। ऑडिशन दे रही थी, पैसे खत्म हो गए थे। 2020 में सबकी तरह मेरे भी पैसे खर्च हो गए थे। ऐसा नहीं था कि घर से कोई फाइनेंशल सपोर्ट ना हो लेकिन 24 साल की उम्र में एक मिडिल-क्लास इंसान होने के नाते यह बात बुरी लगती है कि आपके पास अपना खुद का पैसा नहीं है। ऐसे समय में सिर्फ दो चीजें काम आती हैं, आत्मविश्वास और दृढ़ता। आपको डटे रहना होता है और खुद पर भरोसा रखना होता है। आप जब तक सफल नहीं होंगे, तब तक आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा। ऐसा नहीं था कि '12वीं फेल' से पहले मुझमें टैलेंट नहीं था लेकिन तब कोई भरोसा नहीं कर रहा था। फिल्म जैसे ही चली, सब बदल गया। कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा, जब तक आप सफल नहीं होते।

इंजीनियर या डॉक्टर बनने पर ही रिस्पेक्ट मिलती है, ये गलत

यह सोच कि सिर्फ सीए, इंजीनियर या डॉक्टर बनने पर ही रिस्पेक्ट मिलती है, यह पूरी तरह से गलत है। ऐक्टर, सिंगर, मॉडल, हर प्रोफेशन की अपनी इज्जत होती है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। चाहे आप ट्रेन में तबला या ढोलक ही क्यों न बजा रहे हों, उसमें भी उतनी ही इज्जत है।'

हमेशा वही दिखता है, जिसने बुरा कहा है

सफल होने से पहले रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। सामने वाला आपको जानता नहीं है तो वो पर्सनली आपके खिलाफ कैसे कुछ कर सकता है? अगर रिजेक्शन को पर्सनली लेते हैं तो आप बस अपना ही खून जलाते हैं। उससे कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा मानना है कि अगर कोई जानबूझकर नेगेटिविटी फैला रहा तो मैं उसे लेकर क्या करूंगी, उसे जाने ही दूंगी। कभी-कभी सोचती हूं कि आखिर में सबको मरना ही है तो इतनी नेगेटिविटी का मतलब क्या है? हम खुद ही चीजों को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना लेते हैं। 12वीं फेल के बाद मैंने बहुत प्रेशर ले लिया था। आगे क्या होगा, अगला प्रोजेक्ट क्या होगा। फिर समझ आया कि खुशी से काम है तो तनाव लेने से कोई फायदा नहीं। जिंदगी में परेशानी आई है तो रो-रोकर निकालो या खुशी के साथ। टाइम तो वैसे भी काटना ही है। चार लोग आपके बारे में बुरा बोलेंगे लेकिन चार लोग आपको प्यार भी कर रहे होंगे। अक्सर हमें वही दिखता है, जिसने बुरा कहा है।

विधायक भावना बोहरा ने 2.38 करोड़ की लागत से निर्मित विद्युत उप केंद्र का किया लोकार्पण

कहा भाजपा सरकार में हर घर तक पहुंच रही विकास की रोशनी

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

सेवा,सुविधा और विकास के संकल्प के साथ पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने ग्राम उड़ियाखुर्द (कारेसरा) में क्षेत्रवासियों की एक और बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए 2 करोड़ 38 लाख 13 हजार रुपए की लागत से निर्मित नवीन 33/11 केव्ही विद्युत उप केंद्र का लोकार्पण किया। भावना बोहरा के निरंतर प्रयासों से जनता को मिली इस सुविधा से क्षेत्रवासियों में हर्ष दिखाई दिया।

इस नवीन विद्युत उप केंद्र की स्थापना से कारेसरा, उड़ियाखुर्द, उड़ियाकला, दनिया, बनिया, बिरनपुर, बुधवारा, खपरी, सलिहा एवं बचेड़ी सहित आसपास के ग्रामों के 1300 से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही लो-वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान होगा, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी। विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से अब तक पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में 5 विद्युत उप केंद्र की स्थापना की स्वीकृति मिली है जिसके अंतर्गत 2 करोड़ 39 लाख की लागत से ग्राम बिरनपुर (गांगपुर), 2 करोड़ 38 लाख 13 हजार रुपए की लागत से उड़ियाखुर्द (कारेसरा) विद्युत उप केंद्र का लोकार्पण उनके द्वारा किया जा चुका है वहीं ग्राम पौनी में 1 करोड़ 13 लाख 29 हजार, ग्राम कोयलारीडीह में 1 करोड़ 99 लाख 6 हजार एवं ग्राम भुवालपुर में 1 करोड़ 16 लाख 59 हजार की लागत से विद्युत उप केंद्र निर्माणाधीन है जो जल्द ही पूर्ण हो जाएगा और क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पांडातराई को नवीन उप संभाग बनाया गया है।

इस अवसर पर विधायक भावना बोहरा ने कहा कि डबल इंजन भाजपा सरकार में विकास को रोशनी हर घर और गाँव तक पहुँच रही है। भाजपा सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को सुदृढ़ कर गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। नवीन विद्युत उप केंद्र के प्रारंभ होने से अन्य उप केंद्रों पर भार एवं दबाव भी कम होगा, जिससे क्षेत्र में लो-वोल्टेज, बार-बार ट्रिपिंग और ब्रेकडाउन जैसी समस्याओं में कमी आएगी। इसका प्रत्यक्ष लाभ कृषि कार्यों, सिंचाई व्यवस्था तथा घरेलू उपयोगकर्ताओं को मिलेगा और क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई गति प्राप्त होगी।

उन्होंने आगे कहा कि इस भीषण गर्मी में किसी भी प्रकार के विद्युत अवरोध के कारण जनता को परेशानी न हो इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहें हैं। ट्रांसफार्मर में खराबी उसके विस्थापना जैसे शिकायतों और जल संकट को देखते हुए बोर खनन जैसे कार्यों को प्राथमिकता के साथ पुरे किये जा रहें हैं ताकि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। अधिकारीयों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या व शिकातों को प्राथमिकता से समाधान करें। पंडरिया विधानसभा में जनता की मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़कों का निर्माण, पेयजल योजनाओं का विस्तार, विद्युत आपूर्ति में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन और शिक्षा संस्थानों के विकास जैसे अनेक कार्यों को गति मिली है वहीं प्रशासनिक सुविधाओं का भी निरंतर विस्तार हो रहा है। हमारा उद्देश्य पंडरिया विधानसभा को विकसित, सवर्सुविधायुक्त बनाना है ताकि जनता को इसका लाभ मिल सकें और आर्थिक गतिविधयों को भी बढ़ावा मिले।

भावना बोहरा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से पंडरिया विधानसभा में विकास कार्य तेजी से हो रहें हैं। वर्षो से लंबित परियोजनाएं, विकास कार्य और जनता की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा किया जा रहा है, इसके साथ ही विकास व अधोसंरचना निर्माण के कार्य भी तेजी से किये जा रहे हैं। हाल ही में नगर पालिका पंडरिया को राज्य सरकार द्वारा मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना में शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत नगर में सड़क, नाली, पेयजल, ट्रांसपोर्ट, पार्क, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ई-गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक, सुरक्षा, सोलर एनर्जी, जल संरक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली विकसित किया जाएगा।

कार्यक्रम में जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा की अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा सिंह, जिला पंचायत सदस्य रोशन दुबे, भाजपा जिला मंत्री राघवेंद्र वर्मा, मंडल अध्यक्ष नरेश साहू, राजेंद्र साहू, जनपद सदस्य सुदर्शन कुम्भकार, दारा सिंह राजपूत, धरमपाल कौशिक, बसंत बोहरा, पिंटू सिंह, राजू पारख, टीकम साहू सहित भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

खास खबर

छग चेंबर ऑफ कॉमर्स ने लोगों को साढे आठ लाख रुपये से अधिक के चिल्लर किए वितरित

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

जिले में चिल्हर की समस्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारीयों द्वारा व्यापारियों और लोगों को चिल्हर का वितरण किया गया हैं,इस दौरान शहर के तेरापंथ भवन में लगभग साढ़े 8 लाख रुपए के चिल्हरों का वितरण लोगों को किया गया,जहां बड़ी संख्या में व्यापारी और लोग चिल्हर लेने यहां पहुंचे लगातार चिल्हर रुपए की हो रही समस्याओं को देखते हुए चिल्हर वितरण किया गया हैं।

वहीं इसको लेकर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के राजनांदगांव जिला अध्यक्ष कमलेश बैद ने बताया कि हमारे द्वारा चौथी बार यह चिल्हर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया हैं इस बार साढ़े 8 लाख रुपए के चिल्लर को बांटा जा रहा हैं पर हमने निर्णय लिया है कि व्यापारियों को 2000 तक का चिल्हर देंगे क्योंकि एक ही व्यक्ति को देने से कई लोगों को नहीं मिल पाता है प्रति व्यक्ति और प्रति व्यापारी 2000 तक चिल्हर दिया जा रहा हैं शहर में जो आए दिन चिल्हर की किल्लत हो रही है उसको देखते हुए कलेक्टर से आग्रह किया गया था और चिल्हर अरेंज करा कर दिया गया हैं,10 और 20 का चिल्हर बांटा गया है क्योंकि 5 का चिल्हर अभी बैंक में भी नहीं मिल रहा हैं।

कलेक्टर ने जिला स्तरीय परामशर्दात्री समिति और जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक ली

पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध ऋण उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

राजनांदगांव। कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में मार्च तिमाही 2026 के तहत जिला स्तरीय परामशर्दात्री समिति एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक ली। कलेक्टर ने विभिन्न बैंकिंग एवं शासकीय योजना अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने तथा पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंक एवं विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक हितग्राहियों तक पहुंचाए। उन्होंने एलडीएम द्वारा जून माह में पीएम स्वनिधि महोत्सव एवं खेत बचाओ अभियान के संबंध में जानकारी ली। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, एसएचजी बैंक क्रेडिट लिंकेज, पीएम स्वनिधि, किसान क्रेडिट कार्ड फिशरीज, केसीसी पशुपालन, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई एवं पीएम अजय योजना के प्रगति की समीक्षा गई।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय एवं यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्य शाखा राजनांदगांव के शाखा प्रबंधकों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड मनोज नायक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक राजनांदगांव व प्रभारी निदेशक आरसेटी मुनीश शर्मा, अमित मिश्रा सहित विभिन्न बैंकों एवं विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मात्र 8 माह में बनकर तैयार हुआ 33/11 केव्ही विद्युत उपकेन्द्र, विधायक साहू ने किया शुभारंभ

किसानों और ग्रामीणों को मिलेगा निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति का लाभ

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

ग्राम माटरा में नवनिर्मित 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र का लोकार्पण समारोह उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा विधिवत पूजा-अर्चना एवं फीता काटकर विद्युत उपकेन्द्र के लोकार्पण के साथ किया गया।

इस अवसर पर विधायक दीपेश साहू ने कहा कि यह केवल एक विद्युत उपकेन्द्र का उद्घाटन नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास, किसानों की समृद्धि और ग्रामीण जनजीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि लगभग आठ माह पूर्व इस परियोजना का भूमिपूजन किया गया था और आज यह रिकॉर्ड समय में पूर्ण होकर जनता को समर्पित की जा रही है।

क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा विद्युत उपकेन्द्र

विधायक साहू ने कहा कि ग्राम माटरा सहित पूरे क्षेत्र के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि सामान्यतः इस प्रकार की परियोजनाओं को पूर्ण होने में लंबा समय लगता है, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों, अभियंताओं एवं निर्माण एजेंसियों ने निरंतर निगरानी, समन्वय और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए इसे निर्धारित समय में पूरा किया है।

उन्होंने कहा कि गांवों के विकास का आधार मजबूत अधोसंरचना होती है और सड़क, पानी तथा बिजली किसी भी क्षेत्र की प्रगति की रीढ़ हैं। नया 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र क्षेत्र में बढ़ते विद्युत भार को कम करेगा, वोल्टेज की समस्या का समाधान करेगा तथा किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराएगा। इससे घरेलू उपभोक्ताओं, छोटे व्यापारियों तथा ग्रामीण उद्योगों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

विधायक साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को धरातल पर उतारने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कर जनता तक उसका लाभ पहुंचाती है। ग्राम माटरा का यह विद्युत उपकेन्द्र उसी सोच और संकल्प का परिणाम है। आने वाले समय में क्षेत्र में अधोसंरचना विकास, जन सुविधाओं के विस्तार तथा किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे, जिससे गांवों तक विकास की रोशनी और अधिक मजबूती के साथ पहुंचेगी।

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया वृक्षारोपण

कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान एवं ष्एक पेड़ मां के नामष अभियान से प्रेरित होकर विद्युत उपकेन्द्र परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान विधायक दीपेश साहू ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि पेड़-पौधे जीवन का आधार हैं और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं हरित वातावरण प्रदान करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने नागरिकों से पौधारोपण के साथ-साथ उसके संरक्षण का भी संकल्प लेने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में छग तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, जिला पंचायत दुर्ग की अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, भाजपा मंडल बेरला के अध्यक्ष डोमेंद्र सिंह राजपूत, जनपद पंचायत सदस्य राजेश साहू, पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष डॉ. एनके तिवारी, विधायक प्रतिनिधि किसुन लाल साहू, उकेंद्र साहू, ग्राम पंचायत माटरा के सरपंच देवशरण साहू, सेवा सहकारी समिति माटरा के अध्यक्ष खुमान साहू, थानेश्वर साहू, संजू सिंह राजपूत सहित अनेक जनप्रतिनिधि, विद्युत विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। विद्युत उपकेन्द्र के लोकार्पण पर क्षेत्रवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जनप्रतिनिधियों, विद्युत विभाग तथा प्रशासन के प्रति आभार जताया। ग्रामीणों ने विश्वास व्यक्त किया कि इस उपकेन्द्र के शुरू होने से क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा किसानों एवं आम उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।

बारिश से पहले कवर्धा नगर पालिका परिषद ने कसी कमर, नाला-नालियों की सफाई अभियान जारी

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

नगर पालिका परिषद कवर्धा द्वारा आगामी वर्षाऋतु को ध्यान में रखते हुए शहर में बरसात पूर्व नाला-नालियों की साफ-सफाई की जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष बरसात के दौरान जलभराव की समस्या को रोकने के लिए पूर्व तैयारी के रूप में नाला-नालियों की सफाई कार्य कराया जाता है इस वर्ष भी शहर के सभी प्रमुख नालों, नालियों की सफाई का कार्य समयबद्ध तरीके से कराया जा रहा है। सफाई के दौरान निकाले जा रहे कचरे को तत्काल उठाये जाने हेत निर्देशित किया गया है। ताकि लोगों को समस्याओं का सामना करना ना पड़े। बारिश का पानी बिना किसी रुकावट के नालों के माध्यम से बाहर निकल सके तथा सड़कों, गलियों एवं अन्य रिहायशी क्षेत्रों में बरसात के पानी का भराव न हो। इसके लिए सफाई कार्यों की नियमित निगरानी भी की जा रही है

बरसात के समय न हो परेशानी : चंद्रवंशी

नगर पालिका अध्यक्ष ने सफाई अधिकारी कमर्चारियों को निर्देशित किया है कि प्रतिदिन वार्ड एवं शहर के प्रमुख मागी के नालियों की सफाई करें ताकि लोगों को बरसात के समय बरसाती पानी से परेशानियों का सामना करना ना पड़ें। साफ-सफाई में लापरवाही किसी तरह से ना करे। वार्ड के नागरिकों, शहर के प्रमुख स्थानों पर साफ-सफाई के दौरान लोगों से चर्चा कर सहयोग लें। ताकि सफाई कार्य सुनियोजित ढंग से हो सके। साफ-सफाई के दौरान नालियों के उपर बने चबुतरा को हटाया जाकर सफाई करें। नालियों के उपर स्लैब को हटाये जाने हेतु निर्देशित किया एवं नाली के उपर चबुतरा निर्माण किये जाने वाले के खिलाफ कार्यवाही करने भी निर्देशित किया।

नगर पालिका अध्यक्ष ने कवर्धा शहर के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ एवं जलभराव मुक्त बनाए रखने मे लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने लोगों से नालियों एवं सार्वजनिक स्थानों पर कचरा, प्लास्टिक एवं अन्य सामग्री सड़क पर नहीं फेंकने का निवेदन किया। नगर पालिका परिषद कवर्धा शहरवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा वर्षाऋतु के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए लगातार कार्य कर रही है।

बाल यातना व मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता के लिए विधिक शिविर आयोजित

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

बाल यातना एवं अवैध मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के तत्वावधान में ग्राम ओटेबंद में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न जनहितकारी योजनाओं एवं विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना था।

शिविर में उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए सहायक प्रतिरक्षा अधिवक्ता देवेंद्र साहू ने मानव तस्करी एवं व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों हेतु योजना, 2015 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह योजना मानव तस्करी, जबरन वेश्यावृत्ति, यौन शोषण एवं देह व्यापार के शिकार महिलाओं, बच्चों एवं अन्य व्यक्तियों को विधिक संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। योजना के अंतर्गत पीड़ितों को निःशुल्क कानूनी सहायता, सुरक्षा, पुर्नवास तथा न्यायालयीन कार्यवाही में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाता है।

प्रतिरक्षा अधिवक्ता अमन दुबे ने बताया कि मानव तस्करी एवं यौन शोषण के पीड़ितों को निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ-साथ मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं, जिससे वे सम्मानजनक जीवन की ओर पुनः अग्रसर हो सकें। इसी क्रम में प्रतिरक्षा अधिवक्ता आयुष शुक्ला ने नालसा (एसिड अटैक पीड़ितों को विधिक सेवाएं योजना) के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना एसिड हमले के पीड़ितों को न्याय एवं पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। इसके तहत पीड़ितों को निःशुल्क अधिवक्ता, मुआवजा प्राप्त करने में सहायता, उपचार एवं पुनर्वास संबंधी सुविधाएं तथा अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही में सहयोग प्रदान किया जाता है।

प्रतिरक्षाधिवक्ता पी. राजेश्वरी ने नालसा (बच्चों के लिए बाल-मित्र कानूनी सेवाएं योजना), 2024 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना बच्चों को कानूनी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित, सहज एवं भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है। योजना के तहत बाल पीड़ितों, बाल अपराधियों, अनाथ एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाती है तथा उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाती है। वहीं प्रतिरक्षाधिवक्ता गीता दास एवं दुर्गा साहू ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक क्लीनिक) विनियम, 2011 के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधिक क्लीनिकों के माध्यम से ग्रामीण एवं जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क कानूनी सहायता पहुंचाई जाती है। इन क्लीनिकों में कानूनी परामर्श, आवेदन लेखन, प्रकरणों की जानकारी तथा नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाता है। ग्रामों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, जेलों एवं न्यायालय परिसरों में ऐसे विधिक क्लीनिक संचालित किए जाते हैं।

शिविर के दौरान उपस्थित नागरिकों एवं श्रमिकों को विभिन्न विधिक योजनाओं एवं अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण सहभागिता देखने को मिली तथा उन्होंने विधिक सहायता से जुड़े विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की।

शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता : मंत्री बघेल

नई दृष्टिबिंदु / बेमेरा

सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जनपद पंचायत नवागढ़ के ग्राम पंचायत खेड़ा स्थित शासकीय हाई स्कूल परिसर में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर एसडीएम नवागढ़ श्रीमती दिव्या पोटाई, जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती माया हिरा बारले, मंडल अध्यक्ष राकेश राजपुर, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

शिविर में ग्रामीणों ने राशन कार्ड, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल, बिजली, नामांतरण, सीमांकन एवं कृषि संबंधी समस्याओं सहित विभिन्न मांगों एवं शिकायतों को प्रशासन के समक्ष रखा। प्राप्त आवेदनों का यथासंभव मौके पर ही निराकरण किया गया तथा शेष मामलों के त्वरित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को मिला लाभ : कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, सेवाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तीन हितग्राहियों को उनके नए आवासों की चाबियां प्रदान की गईं। खाद्य विभाग द्वारा पांच हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड वितरित किए गए तथा पांच किसानों को किसान किताब प्रदान की गई। इसके अलावा तीन हितग्राहियों को फूड बास्केट का वितरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए।

शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। कक्षा 12वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 09 विद्यार्थियों को 10-10 हजार रुपये तथा कक्षा 10वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 21 विद्यार्थियों को 5-5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। मत्स्य विभाग द्वारा हितग्राहियों को मछली पकड़ने के जाल भी वितरित किए गए।

जनता से सीधे संवाद कर आवेदन देने के लिए किया प्रेरित : मंत्री दयाल दास बघेल ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों का जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीणों से अपनी समस्याओं एवं मांगों को लिखित आवेदन के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शासन का उद्देश्य प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना है, ताकि आम नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। सुशासन तिहार के माध्यम से समस्याओं का मौके पर सत्यापन एवं त्वरित निराकरण किया जा रहा है तथा पात्र हितग्राहियों को तत्काल योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की दी जानकारी : अपने उद्बोधन में मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है तथा 140 मीट्रिक टन से अधिक धान का उपार्जन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि महतारी वंदन योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बन रही है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।

मंत्री बघेल ने बताया कि प्रदेश में अब तक 14 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में नल-जल योजनाओं को सुदृढ़ बनाकर प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी।

उन्होंने जानकारी दी कि क्षेत्र में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा 1 करोड़ 19 लाख 80 हजार रुपये की लागत से सड़क निर्माण कार्य भी स्वीकृत किया गया है। साथ ही मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आधारभूत सुविधाओं के विस्तार का कार्य लगातार किया जा रहा है।

शिविर में वरिष्ठ जनप्रतिनिधि अजय साहू, जनपद पंचायत बेमेतरा की अध्यक्ष श्रीमती हेमा जय दिवाकर, स्थानीय जनप्रतिनिधि, मंडल पदाधिकारी, विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचगण तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को शासन की योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रभावी पहल की गई।

तमिलनाडु में अन्नामलाई का नया दांव, बीजेपी से बनाई अलग राह, नई पारी की सुगबुगाहट

अन्नामलाई मक्कल इयक्कम से द्रविड़ राजनीति और विजय को चुनौती देने की तैयारी

नई दृष्टिबिंदु / चेन्नई-नई दिल्ली

तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बीजेपी के प्रदेश में सबसे प्रमुख चेहरा रहे के. अन्नामलाई ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने इस्तीफे के साथ ही अन्नामलाई मक्कल इयक्कम नाम से जन-आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। इसे राज्य में सुपरस्टार विजय की राजनीतिक एंट्री और पारंपरिक द्रविड़ दलों के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

इस्तीफे के पीछे की वजह

सूत्रों के अनुसार अन्नामलाई लंबे समय से केंद्रीय नेतृत्व के सामने यह पक्ष रख रहे थे कि बीजेपी को तमिलनाडु में अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव में कोयंबटूर से चुनाव लड़कर और प्रदेश में पार्टी का वोट शेयर 2% से 11% तक पहुंचाकर उन्होंने अपनी रणनीति का असर दिखाया था। जब केंद्रीय नेतृत्व आगामी समीकरणों में AIADMK के साथ गठबंधन के पक्ष में दिखा, तो वैचारिक मतभेद के चलते उन्होंने 2 जून को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उनकी गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष से मुलाकात हुई और केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला स्वीकार कर लिया।

अन्नामलाई मक्कल इयक्कम की रणनीति

अन्नामलाई ने फिलहाल नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कोयंबटूर में एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिटिक्स एंड एथिक्स की स्थापना की जाएगी। इसके जरिए युवाओं को नेतृत्व और नैतिक राजनीति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विश्लेषकों का मानना है कि वे उस युवा वर्ग पर फोकस कर रहे हैं जो द्रविड़ राजनीति से अलग विकल्प चाहता है। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने तमिल प्राइड और तमिल कल्चर को प्रमुख बताया और कहा कि उनका अभियान द्रविड़ राजनीति के खिलाफ है, न कि बीजेपी या केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ।

प्लान-बी की चर्चा

राजनीतिक हलकों में इसे बीजेपी का ह्यप्लान-बीह्न या नया प्रयोग भी माना जा रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी का पारंपरिक ढांचा अब तक व्यापक स्वीकार्यता नहीं पा सका है। ऐसे में अन्नामलाई का स्वतंत्र तमिल चेहरे के रूप में उभरना, अभिनेता विजय के जनाधार और द्रविड़ दलों के वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। चर्चा है कि 5 साल बाद विधानसभा चुनाव से पहले इस आंदोलन को राजनीतिक दल में बदला जा सकता है, जो भविष्य में बीजेपी के साथ गठबंधन का विकल्प बन सके।

आगे की चुनौतियां

इतिहास बताता है कि बीजेपी से अलग होकर कल्याण सिंह, शंकर सिंह वाघेला और उमा भारती जैसे नेता स्वतंत्र राजनीतिक जमीन नहीं बचा पाए। तमिलनाडु में रजनीकांत और कमल हासन जैसे फिल्मी सितारे भी राजनीतिक रूप से पूरी तरह सफल नहीं हो सके। ऐसे में मजबूत संगठन और संसाधनों के बिना 5 साल तक संघर्ष करना अन्नामलाई के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि उनके समर्थन में तमिलनाडु बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं के इस्तीफे की खबरें आ रही हैं, जो उनके जनाधार का संकेत देती हैं।

फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में अन्नामलाई का यह कदम नए समीकरण बना रहा है। आने वाले समय में अन्नामलाई मक्कल इयक्कम किस रूप में आगे बढ़ता है, इस पर सभी दलों की नजर रहेगी।

अवैध शराब के साथ दो अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

राजनांदगांव। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने पुराना बस स्टैंड यात्री प्रतीक्षालय के पास कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बेच रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 53 पौवा देशी प्लेन शराब और बिक्री के 1370 रुपये, कुल 5,610 रुपये का सामान जब्त किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद मकसूद अली, 35 वर्ष, निवासी संबलपुर उड़ीसा और किशोर भट्टाचार्य, 43 वर्ष, निवासी बैतूल मध्य प्रदेश शामिल हैं। पुलिस के अनुसार दोनों आदतन अपराधी हैं। मकसूद अली के खिलाफ रायपुर और डोंगरगढ़ में चोरी के मामले दर्ज हैं। किशोर भट्टाचार्य के खिलाफ चिखली चौकी में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज है।

शादी का झांसा देकर नाबालिग और दो युवतियों से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

पुलिसकर्मी बनकर फंसाता था प्रेमजाल में, संबंध बनाने के बाद मांगता था पैसे

नई दृष्टिबिंदु / डोंगरगांव

थाना डोंगरगांव पुलिस ने शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग और बालिग युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी खुद को पुलिस विभाग से जुड़ा बताकर युवतियों को प्रेमजाल में फंसाता था।

अलग अलग समय पर किया दुष्कर्म : एक नाबालिग और एक बालिग युवती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि तरुण सेन ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर उनके साथ दुराचार किया। आरोपी ने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए। बाद में डरा धमकाकर पैसों की मांग करने लगा।

खुद को बताता था पुलिसकर्मी : आरोपी तरुण सेन, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम माथलडबरी, थाना डोंगरगांव, युवतियों को खुद को पुलिस विभाग से संबंधित बताता था। इसी भरोसे में युवतियां उसके झांसे में आ गईं।

दो केस दर्ज, पॉक्सो एक्ट भी लगा : पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देश पर थाना डोंगरगांव में अपराध क्रमांक 197/2026 धारा 69, 351(1), 308(1) बीएनएस और अपराध क्रमांक 198/26 धारा 137(2), 64(2)(एम), 308(1), 351(1) बीएनएस, 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

24 घंटे में धराया आरोपी : थाना प्रभारी निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी की तलाश की गई। 24 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़कर पूछताछ की गई। अपराध स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

कार्रवाई में सउनि देवकुमार रावटे, प्र.आर. संदीप देशमुख, म.प्र.आर. ललिता तुलावी समेत पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने महिलाओं से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के झांसे में न आएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें।

हार्वेस्टर डीलर 27 लाख की ठगी मामले में गिरफ्तार

जेवरा सिरसा पुलिस ने आरोपी वरुण प्रताप सिंह को भेजा जेल, जांच जारी

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

नए हार्वेस्टर दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले अधिकृत डीलर को जेवरा सिरसा चौकी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी पर करीब 27 लाख रुपये की ठगी का आरोप है।

पैसे लेकर हार्वेस्टर नहीं दिया

पुलिस के अनुसार आवेदक परशुराम साहू, धनेश ढीमर और टीकाराम साहू ने मेसर्स दुर्ग ट्रेक्टर्स के अधिकृत डीलर वरुण प्रताप सिंह के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया कि नया हार्वेस्टर देने के लिए बैंक से फाइनेंस कराई गई राशि सीधे आरोपी की फर्म में ट्रांसफर हुई। साथ ही आवेदकों ने नगद राशि भी दी। इसके बावजूद आरोपी वरुण प्रताप सिंह ने हार्वेस्टर उपलब्ध नहीं कराया और लगातार टालमटोल करता रहा।

27 लाख की धोखाधड़ी

जांच में पाया गया कि आरोपी ने आवेदक परशुराम साहू से हार्वेस्टर के लिए 27 लाख रुपये लेने के बाद भी मशीन नहीं दी। इस पर थाना पुलगांव की चौकी जेवरा सिरसा में अप.क्र. 515/2026, धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

पहले भी दर्ज है केस

गिरफ्तार आरोपी वरुण प्रताप सिंह, उम्र 36 वर्ष, निवासी मालवीय नगर, शांति निकेतन अपार्टमेंट, मोहन नगर है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले भी थाना डौंडी लोहारा, जिला बालोद में अप.क्र. 152/19 धारा 323, 34, 342, 384 भादवि के तहत मामला दर्ज है।

पुलिस को जानकारी मिली है कि आरोपी ने अन्य लोगों से भी हार्वेस्टर दिलाने के नाम पर लाखों रुपये लिए हैं। इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के साथ ऐसी ठगी हुई है तो वे सामने आकर शिकायत दर्ज कराएं।

विश्व पर्यावरण दिवस पर मंत्री यादव ने किया पौधरोपण

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

प्रथम बटालियन परिसर में लगाया पौधा, कहा- पौधारोपण निरंतर चलने वाला अभियान होना चाहिए

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने प्रथम बटालियन, वार्ड-60 दुर्ग परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान अन्य अतिथियों ने भी पौधारोपण किया।

पुलिस जवानों के योगदान की सराहना

मंत्री श्री यादव ने पुलिस जवानों से संवाद करते हुए पर्यावरण संरक्षण में उनकी सहभागिता और योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रकृति संरक्षण बेहद जरूरी है। पौधारोपण केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाला अभियान होना चाहिए।

ये रहे मौजूद

कार्यक्रम में आईजी श्री अभिषेक सांडिल्य, कमांडेंट श्री राजेश कुकरेजा, जिला उपाध्यक्ष श्री शिवेंद्र परिहार, मंडल अध्यक्ष श्री मनमोहन शर्मा, पार्षद श्री गुड्डु यादव, श्री हिमांशु सिंह, श्रीमती मौसमी ताम्रकार, अभिषेक सिंह, धनंजय ठाकुर, मंगेश बोकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

घुमका नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव : कांग्रेस प्रत्याशी फूलमती वर्मा विजयी

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत नगर पंचायत घुमका के अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान की मतगणना बुधवार को स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी व हिन्दी उत्कृष्ट विद्यालय घुमका में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

जारी परिणाम के अनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रत्याशी फूलमती जयकुमार वर्मा ने 1512 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी किरण वर्मा को 1427 मत मिले। आम आदमी पार्टी की अभ्यर्थी अलिशा जोशी को 70 मत प्राप्त हुए। वहीं नोटा में 22 और अंडर वोट 29 दर्ज किए गए।

मतदान मशीन के अनुसार कुल 3060 मत दर्ज किए गए। इस तरह कांग्रेस प्रत्याशी फूलमती जयकुमार वर्मा 85 मतों के अंतर से विजयी रहीं। मतगणना के दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100